

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों को दी सलाह, बोले- एसआईआर पारदर्शी होना चाहिए



नईदिल्ली, संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को राज्य के भाजपा सांसदों से संसद में मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों को सलाह दी है कि वे विधानसभा चुनावों से पहले यह सुनिश्चित करें कि राज्य में चल रहा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान सरल और पारदर्शी बना रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसआईआर को ज्यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि योग्य मतदाताओं को शामिल किया जाए और जो योग्य नहीं हैं उन्हें हटाया जाए और यह संदेश ज़मीनी स्तर तक पहुंचना चाहिए। संसद में सांसद प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए उन्होंने पार्टी की ताकत का लाभ उठाने और वर्षों से बनी गति को बनाए रखने को कहा। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में पार्टी को केंद्रित रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल में किसी तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगातार चौथी बार सरकार बनाने से रोकने के लिए रणनीति पर चर्चा भी की। उन्होंने सांसदों को याद दिलाया कि 2011 में बंगाल में केवल 3 विधायक थे, और 2016 तक काफी बढ़ गए हैं।

योगीराज में घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू, उत्तर प्रदेश में रोहिंया, बांग्लादेशी खोजे जाएंगे, होगी कार्रवाई

पीआईबी उत्तर प्रदेश में कथित रोहिंया और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। मुख्यमंत्री को आदेशानुसार, प्रत्येक संभाग में हिरासत केंद्र स्थापित होंगे। अवैध प्रवासियों की पहचान, सत्यापन और निर्वासन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान नेपाल सीमा और प्रमुख शहरी केंद्रों पर केंद्रित है, जो अवैध विदेशी नागरिकों के विरुद्ध एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कथित रोहिंया और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है और राज्य के हर संभाग में हिरासत केंद्र स्थापित

लाल किला ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी वानी की रिमांड बढी

पीआईबी दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला विस्फोट मामले के मुख्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ा दी। वानी को अदालत में पेश किया गया क्योंकि प्रधान सत्र एवं जिला न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना द्वारा 27 नवंबर को दी गई उसकी सात दिन की रिमांड आज समाप्त हो गई। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड निवासी वानी को एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर में गिरफ्तार किया था। उस पर 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट से पहले ड्रोन में बदलाव करके हमले करने और रॉकेट बनाने की कोशिश करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का आरोप है। इस विस्फोट में 13 लोग मारे गए थे। एनआईए ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार - एनआईए ने लाल किला विस्फोट मामले में अब तक सात प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में कथित आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने एक हंड्रेड 120 कार के अंदर एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) का इस्तेमाल करके खुद को उड़ा लिया था। यह मामला एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है जिसका जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पर्दाफाश किया था।

पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूस के साथ सैन्य रसद समझौता

सेना को होगा फायदा आज आएंगे पुतिन नईदिल्ली, संवाददाता।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने मंगलावर को भारत के साथ एक जरूरी सैन्य रसद समझौते को मंजूरी दी है, जिसे एक बड़ा रक्षा सहयोग बताया जा रहा है। समझौते को रसद समर्थन के पारस्परिक आदान-प्रदान (आरईएलओएस) संधि के रूप में जाना जाता है। यह मूल रूप से 18 फरवरी को भारत-रूस की सरकारों के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। समझौते को लेकर स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं, और हम उन्हें महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि आज समझौते का अनुसमर्थन पारस्परिकता और निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विकास की दिशा में एक और कदम है। बता दें कि समझौते को अनुमोदन के लिए पिछले सप्ताह रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा निचले सदन में भेजा गया था। आरईएलओएस संधि दोनों देशों



कि भारत के साथ हमारे संबंध रणनीतिक और व्यापक हैं, और हम उन्हें महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि आज समझौते का अनुसमर्थन पारस्परिकता और निश्चित रूप से हमारे संबंधों के विकास की दिशा में एक और कदम है। बता दें कि समझौते को अनुमोदन के लिए पिछले सप्ताह रूसी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन द्वारा निचले सदन में भेजा गया था। आरईएलओएस संधि दोनों देशों

लोकसभा में सुचारु रही प्रश्नकाल की कार्यवाही

जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में होगा



नईदिल्ली,एजेंसी संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र का पहला दो दिन काफी हंगामेदार रहा। हालांकि, आज लोकसभा और राज्यसभा में सामान्य कार्यवाही देखने को मिली। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के कार्यवाही सुचारु रूप से संपन्न हुई। इससे पहले दो दिन तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही। इसके अलावा कई गंभीर मसलों पर सांसदों ने अपनी बात रखी है। लोकसभा की कार्यवाही केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मंगलवार को लोकसभा को सूचित किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने बुधवार को कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने से जीएसटी क्षतिपूर्ति कर समाप्त करने के बाद भी कर का बोझ समान रहेगा। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए सीतामरण ने कहा कि यूई जीएसटी कानून में अधिकतम कर दर 40 प्रतिशत तय है, इसलिए यदि जीएसटी उपकर हटा दिया जाता है और उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है तो तंबाकू पर कुल कर बोझ वर्तमान स्तर से कम हो जाएगा।

फर्जी खबरों और एआई जनित डीपफेक वीडियो पर रोकथाम के लिए कड़े नियम बनेंगे जल्द

फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार फर्जी खबरों और एआई जनित डीपफेक वीडियो पर रोकथाम के लिए और इस बाबत संस्थागत प्रणाली बनाने के लिए नए नियम बना रही है। वैष्णव ने लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि फर्जी खबरों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डीप फेक पर सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की जरूरत है। फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और यह गंभीर विषय है।

कि आगामी जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में होगा, जिसकी शुरुआत 2026 में मकान सूचीकरण और आवास संबंधी ऑकड़े एकत्र करने से होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30



दिनों की अवधि में, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय समय-सीमा के आधार पर पूरा किया जाएगा। जनसंख्या गणना से जुड़ा दूसरा चरण फरवरी 2027 में निर्धारित है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक प्रश्न के उत्तर में, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पुनः पुष्टि की कि 1 मार्च, 2027 को रात्रि 12:00 बजे पूरे देश में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि मानी जाएगी। हालाँकि, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए, जनसंख्या गणना सितंबर 2026 में ही की जाएगी और 1 अक्टूबर, 2026 को संदर्भ तिथि माना जाएगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के मुताबिक, देश में जल्द ही सभी क्षेत्रों में 4जी कनेक्टिविटी पहुंचाने का लक्ष्य है और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों समेत कई जगहों पर अगले साल तक 12 हजार 4जी टॉवर लगाए जाएंगे।

सरकार ने खत्म की मोबाइल फोन में संचार साथ ऐप पहले से इंस्टॉल करने की अनिवार्यता

नईदिल्ली। एजेंसी केंद्र सरकार ने संचार साथ ऐप को लेकर खड़े हुए विवाद के बाद बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भारत में बिज्जी के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले सभी नए मोबाइल फोन में इस ऐप को पहले से ही इंस्टॉल करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया है। दरअसल, इस अनिवार्यता को विपक्षी दलों ने लोगों की जासूसी बताते हुए उनके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करार दिया था। उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था। संचार साथी ऐप सरकार द्वारा बनाया गया एक सुरक्षा टूल है, जिससे उपयोगकर्ता अपने चोरी या खोए हुए मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर सकते हैं। इस ब्लॉकिंग के बाद फोन कहीं भी इस्तेमाल होगा तो एजेंसियां उसकी लोकेशन पता कर सकेंगी। ऐप में कई फीचर हैं, जहां लोग फर्जी कॉल, नकली एसएमएस या गलत व्हाट्सएप मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, उपयोगकर्ता अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर भी आसानी से चेक कर सकते हैं।

राज्यसभा में विपक्षी हंगामा : पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी: पर्यावरण मंत्री

संवाददाता सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में दावा किया कि दिल्ली में 400 एक्जुआईड से अधिक स्तर वाले दिनों में कमी आयी है, वहीं 2016 की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आयी है। दिल्ली के पर्यावरण को सरकार के लिए चिंता का विषय बताते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह बात मणिपुर से संबंधित एक संकल्प पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कही। देशभर के राजभवनों का नाम 'लोक भवन' करने संबंधी गृह मंत्रालय के 25 नवम्बर के निर्देश का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को शून्यकाल के दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सदस्य डोला सेन द्वारा उठाए जाने के बाद सदन में तीखी नोकझोंक हुई।



शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बांग्ला में डोला सेन ने कहा, "सबसे पहले हम यह कहना चाहते हैं कि न तो संसद, विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी हैज और तो और महोदय, वे आपसे भी इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।" अपनी बात रखने के दौरान डोला सेन ने मनरेगा सहित अन्य मुद्दों का भी जिक्र किया। तब सभापति ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदस्य अपने मूल विषय पर ही बोलें और विषय से

ली जाएं। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने नड्डा से सहमति जताते हुए दोहराया कि विषय से हटकर कहा गया कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। राज्यसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्य मेधा विश्वास कुलकर्णी ने गैर-हलाल उत्पादों पर से 'हलाल प्रमाणपत्र' वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह हमारे संविधान के खिलाफ है, जो सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक आस्था का पालन करने का अधिकार देता है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने डोला सेन के समर्थन में कहा कि उन्होंने कोई भी अपमानजनक शब्द नहीं बोला है। सब कुछ विषय से जुड़ा हुआ है। और यह विषय आपके कार्यालय में जांचने के बाद ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई थी।

विश्व होमलैंड सुरक्षा विभाग आगे की सूची जल्द ही जारी की जाएगी

अमेरिका में गोलीबारी के बाद ट्रंप सख्त, 30 से अधिक देशों पर यात्रा प्रतिबंध की तैयारी

एजेंसी। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में अति सुरक्षित व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप विचाराधीन विस्तारित यात्रा प्रतिबंध के तहत 30 से अधिक देशों के विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके लिए ट्रंप प्रशासन 30 देशों को संशोधित सूची में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। आगे इसमें कई अन्य देशों को भी शामिल किए जाने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, होमलैंड सुरक्षा विभाग आगे की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। यह अंतिम चरण में है और जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती



है। विभाग के सचिव क्रिस्टी नोएम ने बताया कि उन्होंने ट्रंप के साथ बैठक में «पूर्ण यात्रा प्रतिबंध» का प्रस्ताव रखा था। नोएम ने कहा कि उन्होंने हर उस देश को प्रतिबंधित सूची में जोड़ने की सिफारिश की है जो अमेरिका को

हथारों, जोंक और अधिकार के दीवानों से भर रहा है। ट्रंप ने जून में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया और सोमालिया सहित 12 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने समेत 7 अन्य देशों से प्रवेश को आंशिक रूप से

प्रतिबंधित करने संबंधी एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यह आदेश कोलोराडो में एक यहूदी-विरोधी बमबारी के बाद आया था। उसे एक मिस्र के नागरिक ने अंजाम दिया था, जिसका पर्यटक बीजा समाप्त हो चुका था। वाशिंगटन गोलीबारी के बाद वेनेजुएला, ईरान और अफगानिस्तान के लोगों के नागरिकता समारोह रद्द कर दिए गए हैं। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस के पास वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों पर अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लकनवाल ने गोलीबारी की थी, जिसमें 20 वर्षीय गार्ड सदस्य सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई, जबकि 24 वर्षीय एंड्रयू वोल्फ गंभीर रूप से घायल हैं।

मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान एमएच370 की खोज फिर शुरू होगी



कुआलालंपुर, एजेंसी। विमान हादसों की कड़ी में मलेशिया का एमएच370 विमान हादसा एक आश्चर्यजनक मामला है, जिसमें विमान आसमान से अचानक लापता हो गया था। विमान हादसे के एक दशक बाद भी अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं मिली है। ऐसे में इसकी जांच दोबारा से शुरू की जाएगी। मलेशियाई अधिकारियों ने कहा है कि मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान संख्या एमएच370 के मलबे की खोज 30 दिसंबर को फिर से शुरू होगी। हादसे के समय विमान में 239 लोग सवार थे। विमान की खोज इस साल मार्च में शुरू हुई थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उसे स्थगित कर दिया गया था। अब नई सिरे से खोज 55 दिन चलेगी। मलेशिया के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि ओशन इन्फिनिटी कंपनी इस खोज का नेतृत्व करेगा। अगर मलबा नहीं मिला तो वह कोई शुल्क नहीं लेगा। परिवहन मंत्री लोके सियु फूक ने बताया कि अगर मलबा मिल जाता है, तो कंपनी को 7 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे।

लक्ष्मी राजवाड़े ने भटगांव विधानसभा के शिवप्रसाद नगर धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण

रायपुर। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज भटगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शिवप्रसाद नगर स्थित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीदी की व्यवस्था, किसानों को दी जा रही सुविधाओं, मापक यंत्रों, तौल व्यवस्था तथा धान उपाजन की संपूर्ण प्रक्रिया का बारीकी से अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने केंद्र में पहुंचे किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। किसानों ने उन्हें बताया कि धान खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से चल रही है और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने किसानों से समर्थन मूल्य, तुलाई की गति, बारदाने की उपलब्धता तथा परिवहन व्यवस्था को लेकर भी फीडबैक लिया।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े कहा कि राज्य सरकार किसानों से समय पर और पारदर्शी तरीके से धान खरीदी के लिए कृतसंकल्पित है। किसानों की मेहनत और उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि केंद्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग

की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, कृषकगण और ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

घर के आंगन में बने कुएं में डूबने से दो बच्चियों की मौत, परिवार पर दूटा दुखों का पहाड़

जांजगीर चांपा ।

जिले के ग्राम कनाई से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक घर के आंगन में बने खुले कुएं में खेलते समय दो नाबालिग बच्चियों की डूबकर मौत हो गई। परिवार के लोगों ने काफी देर तलाश के बाद कुएं से शवों को बाहर निकाला। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बता दें कि मृतक बच्चियों की पहचान अस्मिता दरवेश (6 वर्ष) और प्रिंशी दरवेश (4 वर्ष) के रूप में हुई है। अस्मिता के पिता का नाम छत्रप्रकाश और प्रिंशी के पिता चंद्रप्रकाश बताया गया है। दोनों ही बच्चियाँ दो भाईयों की बेटियाँ थीं। जानकारी के अनुसार, बच्चियां घर के बाड़ी में खुले कुएं के पास



खेल रही थीं। परिजनों ने जब उन्हें नहीं देखा तो खोजबीन शुरू की। कुएं की तलाशी लेने पर बच्चियों को बाहर निकाला गया और तुरंत जिला अस्पताल जांजगीर लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय

पुलिस ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि हदसा असावधानी के कारण हुआ। घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और मामले की छनबीन कर रहे हैं। गांव में इस दुखद घटना से मातम पसरा हुआ है।

विश्व एड्स दिवस पर रायगढ़ जिला न्यायालय परिसर में जागरूकता शिविर

रायगढ़। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर 01 दिसंबर को रायगढ़ जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जितेंद्र कुमार जैन के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ की सचिव एवं न्यायाधीश अंकिता मुदलियार के नेतृत्व में आयोजित किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य एचआईवी संक्रमण एवं एड्स के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना, मिथकों का निराकरण करना और लोगों को सुरक्षित व्यवहार व कानूनी सहायता संबंधी जानकारी प्रदान करना था। जिला न्यायालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्राधिकरण के कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के सदस्य, विधि महाविद्यालय के छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। शुरुआत में उपस्थित लोगों को विश्व एड्स दिवस के महत्व, इस वर्ष की थीम और एड्स रोकथाम से संबंधित वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में बताया गया। शिविर में एचआईवी संक्रमण के फैलने के तरीकों, सुरक्षित उपायों और समय पर टेस्टिंग एवं उपचार की आवश्यकता पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति भी सही उपचार के साथ सामान्य जीवन जी सकते हैं और इसके लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इसके साथ ही, समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने तथा संक्रमित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की अपील की गई। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा एवं सालसा की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की गई। इसमें विशेष रूप से आपदा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता, यौन शोषण एवं मानव तस्करी के पीड़ितों हेतु कानूनी सेवाएं, श्रमिकों एवं कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायता योजनाएं, संवाद, डॉन और जागृति जैसी प्रमुख पहल शामिल रही। कार्यक्रम में बताया गया।

मोहला-मानपुर में बाघ की दस्तक से दहशत, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट

मोहला-मानपुर । जिले में बीते कुछ वर्षों से जंगली जानवरों की बढ़ती सक्रियता ने वन विभाग और ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पहले हाथियों का आतंक, फिर तेंदुए की आमद और अब बाघ के पहुंचने की पुष्टि ने वन क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ताजा मामला दक्षिण वन परिक्षेत्र का है, जहां बाघ द्वारा एक पालतू गाय का शिकार किए जाने के बाद वन विभाग ने न केवल पुष्टि की है बल्कि पूरे इलाके में सघन निगरानी भी शुरू कर दी है। गाय का शिकार और पगमार्क से पृष्ठ हुई बाघ की मौजूदगी वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) दिनेश पटेल ने बताया कि 1 दिसंबर को मानपुर दक्षिण वन परिक्षेत्र अंतर्गत औंथी तहसील के ग्राम नवागढ़ में एक पालतू गाय को किसी जंगली जानवर द्वारा मारे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय वन अमला मौके पर पहुंचा। जांच के दौरान गांव से लगे वन भूमि कक्ष क्रमांक 1080 में बाघ के पगमार्क स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। वहीं गांव से थोड़ी दूरी पर जंगल में गाय की क्षत-विक्षत लाश भी मिली, जिससे यह साफहो गया कि यह हमला किसी भारी-

भरकम शिकारी द्वारा किया गया है। DFO पटेल ने कहा कि तेंदुए और चीते जैसे जानवर इतनी बड़ी गाय को इतनी दूर खींचकर ले जाने में सक्षम नहीं होते, इसलिए पगमार्क और मौके की परिस्थिति को देखते हुए हमला बाघ द्वारा किए जाने की पुष्टि हुई है। दोबारा आने की आशंका, इलाके में लगाए गए कैमरे छस्रह पटेल ने बताया कि चूंकि बाघ पहले ही शिकार कर चुका है, ऐसे में इस स्थान पर उसके दोबारा आने की प्रबल संभावना है। इसी कारण आज दक्षिण वन परिक्षेत्र के नवागढ़ गांव से सटे क्षेत्र में तीन अलग-अलग स्थानों पर पेड़ों पर कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों पर बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वन विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में कैमरे में बाघ की तस्वीरें और उसका मूवमेंट साफहो सकेगा। महाराष्ट्र सीमा से संभावित आमद मोहला-मानपुर जिला महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है और कई बार वन्य जीव दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करते रहे हैं। प्रभागीय वन अधिकारी पटेल ने आशंका जताई कि बाघ महाराष्ट्र के जंगलों से विचरण करते हुए

छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी इसी ओर इशारा कर रही है। विभाग जल्द ही बाघ के उम्र, आकार और मूवमेंट की दिशा से संबंधित अधिक जानकारी जुटाने की उम्मीद कर रहा है। ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग ने जारी की चेतावनी बाघ की आमद की खबर से नवागढ़ और आसपास के गांवों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों को अकेले जंगल में नहीं जाने, समूह में ही आवाजाही करने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वन विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही हैं। विभाग ने ग्रामीणों से कहा है कि किसी भी असामान्य गतिविधि, जानवर के दिखने या आवाज सुनाई देने पर तुरंत वन अमले को सूचना दें। पांच-छह सालों से बढ़ रही जंगली जानवरों की गतिविधि मोहला-मानपुर में जंगली जानवरों की आमद कोई नई बात नहीं, लेकिन बीते पांच-छह सालों में यह तेजी से बढ़ी है। पहले हाथियों का इस इलाके में आना दुर्लभ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हाथी कई बार बस्तियों में घुसकर फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं।

तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, पांच लोग घायल

बिलासपुर । सड़क हादसों पर लगातार लगाम लगाने के प्रयासों के बावजूद जिले में लापरवाह ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला नन्धापारा सिरगिट्टी का है, जहां ग्राम छत्तौना से लौट रहे पांच लोग एक तेज रफ्तार कार की लापरवाही का शिकार बन गए। हादसे में सभी घायल हुए, जिन्हें न्यू जनता हॉस्पिटल तिफ्फा में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद पीड़ितों ने चकरभाठा थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित युवक, नयापारा सिरगिट्टी निवासी मजदूर ने पुलिस को बताया कि 15 नवंबर को वह अपने चाचा के गांव छत्तौना में हुए बर्थडे कार्यक्रम में शामिल होने गया था। उसके साथ उसका दोस्त जितेंद्र यादव भी था। दोनों 16 नवंबर की सुबह अपने घर लौटने के लिए ऑटो से निकले। जब वे पंचायत भवन छत्तौना के पास पहुंचे। तभी पीछे से आ रही कार क्रमांक CG 10 BT 7503 के चालक ने तेजी और लापरवाही



पूर्वक वाहन चलाते हुए ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो पलट गया और उसमें बैठे सभी लोग सड़क पर गिर पड़े। हादसे में शिकायतकर्ता के दाहिने हाथ और दाहिने पैर में चोट आई। उसका दोस्त जितेंद्र

यादव भी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं अन्य सवारियां कुंवारा बाई, अवंश श्रृंगवंशी और दीपक दुबे भी घायल हुए। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पीड़ितों के परिजनों को दी और मौके से एंबुलेंस एवं निजी वाहनों की मदद से

सभी को न्यू जनता अस्पताल तिफ्फा पहुंचाया गया। पीड़ितों का अस्पताल में इलाज लगभग दो सप्ताह तक चला। 30 नवंबर को सभी को डिस्चार्ज किया गया इसके बाद 1 दिसंबर को शिकायतकर्ता चकरभाठा थाना पहुंचा और आरोपी कार चालक के खिलाफकार्रवाई की मांग की। उसने बताया कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी आसपास के कई लोग हैं, जिन्होंने दुर्घटना को अपनी आंखों से देखा। पीड़ित ने यह भी उल्लेख किया कि रिपोर्ट लिखवाने के बाद पढ़कर सुनाई गई और वही दर्ज की गई, जैसा उसने बताया था। अब वह पुलिस से इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। यह हादसा फिर एक बार साबित करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही भरी ड्राइविंग सिर्फनिर्णयों का उल्लंघन नहीं बल्कि लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। पुलिस अब इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई कर रही है।

स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण भोजन हेतु रसोइयों को मिल रहा उन्नत फॉस्टेक प्रशिक्षण

धमतरी। नियंत्रक महोदय, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के मार्गदर्शन में जिले में मध्यान्ह भोजन रसोइयों का फॉस्टेक (फॉस्टेक) प्रशिक्षण 1 से 10 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से संचालित इस प्रशिक्षण में धमतरी जिले के लगभग 1132 शासकीय विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी आवश्यक मानकों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण , नई दिल्ली से अधिकृत प्रशिक्षक धमतरी पहुंचे हैं। प्रशिक्षण के दौरान

रसोइयों को मध्यान्ह भोजन के निर्माण, भंडारण और परोसने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली खाद्य सुरक्षा मानक, स्वच्छता नियम, हाथ धोने की विधि, बर्तनों की सफाई, साफ पानी का उपयोग तथा पृष्ठ प्वाइजनिंग की रोकथाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारीयों से अवगत कराया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों को ऑडियो-वीडियो माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया, जिससे रसोइयों को व्यावहारिक समझ विकसित करने में सहायता मिली। आज 2 दिसंबर को भखराा में आयोजित प्रशिक्षण सत्र में 130 रसोइयों ने सक्रिय सहभागिता की। कार्यक्रम में

विकासखंड शिक्षा कार्यालय कुरूद से गुरुनारायण साहू, अभिहित अधिकारी सर्वेश कुमार यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा तथा नमूना सहायक गिरजा शंकर वर्मा उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रशिक्षण पूर्ण होने पर सभी रसोइयों की प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे, जिससे जिले में मध्यान्ह भोजन वितरण की गुणवत्ता और अधिक सुदृढ़ होगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस प्रशिक्षण से रसोइयों की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे बच्चों को स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के राज्य शासन के उद्देश्य को और मजबूती मिलेगी।

गाली-गलौज के विवाद पर युवक की हत्या, 1 आरोपी और दो नाबालिग समेत तीन गिरफ्तार

रायपुर। राजधानी रायपुर के उरला थाना क्षेत्र में गाली-गलौज की बात पर एक युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले तीन आरोपियों एक वयस्क और दो विधि के साथ संघर्षरत बालकों—को पुलिस ने घटना के चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह हत्या ग्राम गुमा स्थित सिंघानिया पुट्रोले पंप के पास हुई थी, जहां मृतक पुष्कर सिंह गोंड को खून से लथपथ हालत में पाया गया था। पुलिस की त्वरित जांच, सीसीटीवी विश्लेषण और तकनीकी इनपुट के आधार पर तीनों आरोपियों को दबोच लिया गया। घटना का विवरण दिनांक 30 नवंबर की रात पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गुमा में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ पड़ा है। उरला पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। युवक के शरीर पर हथियार से किए गए वार के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हालात देखकर यह साफ था कि

किसी तेज धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की गई है। मृतक की पहचान प्रारंभिक स्तर पर नहीं हो पाई थी। वरिष्ठ अधिकारियों—पुलिस उप महानिरीक्षक एवं एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पहचान और जांच शुरू एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा उरला थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी दौरान मृतक की पहचान पुष्कर सिंह गोंड, पिता कन्हैया गोंड (24), निवासी ग्राम चकमी रैयत थाना करंजिया, जिला डिंडोरी (म.प्र.) हाल-प्राइम इस्पात, ग्राम गुमा के रूप में हुई। टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरो की मदद से सदिग्ध व्यक्तियों की तलाश शुरू की। कुछ ही घंटों में घटना में संलिप्त आरोपी विनाद चतुर्वेदी (18 वर्ष) के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।

रासायनिक नहीं प्राकृतिक खेती ने तुलसीराम को दी नई पहचान



रायपुर। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के विस्तार से उन्हें नई दिशा मिली किसान तुलसीराम मौर्य। मिशन के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद तुलसीराम ने श्री विधि से कुटकी, कोसरा और रागी की खेती शुरू की। नई तकनीक और प्राकृतिक तरीकों ने उनके खेतों में नई जान डाल दी। उत्पादन बढ़ा, मिट्टी की गुणवत्ता सुधरी और रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह बंद हो गया।

खेती की लागत में काफी आई, कमी जैविक उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल रहा है

किसान तुलसीराम मौर्य जो दतेवाड़ा जिले के गौदम विकासखंड के ग्राम छिंदनार (बड़े पारा) निवासी हैं आज प्राकृतिक खेती के सफल उद्यमी बनकर क्षेत्र के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। पहले वे परंपरागत खेती में अधिक खर्च और कम उत्पादन से परेशान रहते थे। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग के कारण मिट्टी की ताकत भी लगातार घट रही थी। इसी दौरान उन्होंने गोबर खाद, जीवामृत और नीम-लहसुन आधारित जैविक घोल का प्रयोग शुरू किया, जिससे खेती की लागत में काफी कमी आई। साथ ही प्राकृतिक तरीके से उगाई गई सब्जियों में भिंडी, करेला, लौकी, टमाटर, मिर्च आदि से उन्हें रोजाना आय होने लगी। बाजार में उनकी उपज को जैविक उत्पाद होने के कारण बेहतर मूल्य भी मिलता है।

ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं

तुलसीराम की सफलता देखकर गांव के 20 से अधिक किसान भी श्री विधि और प्राकृतिक खेती अपनाने लगे हैं। गांव की महिलाएं भी जैविक घोल तैयार करने में सक्रिय होकर आजीविका से जुड़ रही हैं। उत्कृष्ट कार्य के लिए कृषि विभाग द्वारा तुलसीराम मौर्य को आदर्श कृषक सम्मान भी दिया गया है। अपने भविष्य की योजनाओं को साझा करते हुए वे बताते हैं कि अब वे 5 एकड़ क्षेत्र को पूर्णतः जैविक खेती क्षेत्र में विकसित करने के साथ-साथ जैविक अनाज प्रोसेसिंग यूनिट और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

प्राकृतिक खेती ने उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान से भरा नया जीवन दिया

प्राकृतिक खेती एक रसायनमुक्त पारंपरिक कृषि पद्धति है जो मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता को बढ़ावा देती है। यहां रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, गुड़, नीम और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से बने उत्पादों का उपयोग करते हैं।

अगले महीने रायपुर में होगा साहित्य उत्सव, देश भर के 100 से अधिक साहित्यकार जुटेंगे

साहित्य उत्सव से छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर। नए वर्ष की शुरुआत के साथ छत्तीसगढ़ एक बार फिर साहित्यिक ऊर्जा से सराबोर होने को तैयार है। आगामी महीने रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन नवा रायपुर में 23 से 25 जनवरी तक होगा, जिसमें देश भर से 100 से अधिक प्रतिष्ठित साहित्यकार शामिल होंगे। राज्य स्थापना के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा इस आयोजन की परिकल्पना की गई थी। उनकी यह परिकल्पना अब साकार रूप लेने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के



अध्यक्ष श्री शंशाक शर्मा, जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वरिष्ठ साहित्यकार श्री सुशील त्रिवेदी, डॉ. चितरंजन कर, श्री गिरीश पंकज, डॉ. संजीव बक्शी, श्री प्रदीप श्रीवास्तव और श्रीमती शकुंतला तरार उपस्थित थे।

लोगो अनावरण के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के

25 वर्ष पूरे होने पर पूरा प्रदेश रजत महोत्सव मना रहा है, और रायपुर साहित्य उत्सव उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह उत्सव न केवल छत्तीसगढ़ को, बल्कि पूरे देश के मूर्धन्य साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, जहाँ उनके अनुभव, विचार और रचनात्मक धारा से अवगत होने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को साहित्यिक जगत में एक नई पहचान प्रदान करेगा तथा जनसमुदाय को साहित्य, लेखन और पठन-पाठन की ओर प्रेरित करेगा। साथ ही यह उत्सव राज्य की विकास योजनाओं के लिए भी सकारात्मक सामाजिक चेतना और विमर्श का मंच बनेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने किया

उत्सव के लोगो का अनावरण उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संकल्पना पर आधारित इस आयोजन की व्यापक कार्ययोजना मात्र दो माह में तैयार की गई है। यह तीन दिवसीय महोत्सव 23, 24 एवं 25 जनवरी 2026 को जनजातीय संग्रहालय के समीप आयोजित होगा। इस उत्सव में कुल 11 सत्र शामिल होंगे। इनमें 5 समानांतर सत्र, 4 सामूहिक सत्र, और 3 संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें साहित्यकारों एवं प्रतिभागियों के बीच सीधा संवाद और विचार-विमर्श होगा। अगले महीने आयोजित होने जा रहे रायपुर साहित्य उत्सव के लोगो में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक प्रभावशाली प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। यह लोगो न सिर्फ राज्य की पहचान को दर्शाता है, बल्कि

बस्तर की जैव-विविधता, जनजातीय परंपराओं, और छत्तीसगढ़ की आत्मा माने जाने वाले सल्फी पेड़ की सांस्कृतिक महत्ता को भी सशक्त रूप में उजागर करता है।लोगो में सल्फी के पेड़ को छत्तीसगढ़ राज्य के नक्शे का रूप देकर यह संदेश दिया गया है कि राज्य की सभ्यता, संस्कृति और साहित्य सदियों से इसी भूमि की जड़ों से पोषित होते आए हैं। सल्फी का यह पेड़ आदिकाल से चली आ रही पौराणिक परंपराओं, भाईचारे और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। जनजातीय समाज के जीवन में गहराई से रचे-बसे इस पेड़ को साहित्य उत्सव के लोगो में शामिल करने से यह संदेश भी मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय साहित्य, लोकविश्वास और पारंपरिक ज्ञान-धारा आज भी समकालीन साहित्यिक प्रवाह के केंद्र में है।



रायपुर।भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है।प्रेक्टिस के दौरान इन खिलाड़ियों को रोहित-विराट के सामने गेंद डालने का मौका मिलेगा। वहीं ऋतू मोदी की मौजूदगी में हुई छत्तकट्टक कॉन्फ्रेंस में तैनात 2 हजार पुलिसकर्मियों को रोक लिया गया है। वनडे मैच के लिए तैनाती की गई है। वहीं 30 नवंबर को

शाम 5.30 बजे से भारतीय टीम प्रैक्टिस करने उतरे हुए है। बता दें कि प्रैक्टिस के दौरान आम दर्शकों की एंट्री बैन है, जबकि छत्तगढ़ के कार्डधारी ही स्टेडियम में प्रवेश कर सकेंगे। दोनों टीमों के लिए 30 स्थानीय खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है।प्रेक्टिस के दौरान इन खिलाड़ियों को रोहित-विराट के सामने गेंद डालने का मौका मिलेगा। वहीं ऋतू मोदी की मौजूदगी में हुई छत्तकट्टक कॉन्फ्रेंस में तैनात 2 हजार पुलिसकर्मियों को रोक लिया गया है। वनडे मैच के लिए तैनाती की गई है। वहीं 30 नवंबर को

गांजा परिवहन करते एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार, पूछताछ जारी

रायपुर । जिले की तिल्दा नेवरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 2 किलो 770 ग्राम गांजा जब्त किया है। मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है।मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 02.12.2025 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि मोसा. अपाचे क्रमांक सीजी 04 एन.जेड. 9660 का चालक अवैध मादक पदार्थ परिवहन कर तिल्दा की ओर आ रहा है जिसे थाना तिल्दा नेवरा पुलिस के द्वारा चलित नाकेबन्दी के माध्यम से रुकवाकर विधिवत् कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुये तलाशी लेने पर आरोपी के पास से कुल वजन 02 किलो 770 ग्राम मादक पदार्थ गांजा जिसका अनुमानित कीमत 45 हजार रुपये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन को जप्त किया गया है। मामले में आरोपी के विरुद्ध थाना तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा धारा 20(बी) नाकटोटिक एक्ट कायम किया गया। आरोपी गोलु देवार को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।

धमतरी जिले में धान खरीदी ने पकड़ी रफ्तार

धमतरी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अभियान के अंतर्गत धमतरी जिला प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जिले के 11 उपार्जन केंद्रों में किसानों द्वारा उत्पाहपूर्वक धान विक्रय किया जा रहा है। अब तक कुल 21,660 किसानों से 10,06,755.20 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गए धान के एवज में किसानों को लगभग 2,38,85,73,000 की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे किसानों के खाते में समय पर भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।केंद्रवार खरीदी की स्थिति में नगरी, कुरुद, मगरलोड, धमतरी और कोरां केंद्र प्रमुख रूप से आगे हैं। नगरी में 1,74,666.40 क्विंटल, कुरुद में 1,19,246.40 क्विंटल, मगरलोड में 1,29,231.20 क्विंटल तथा धमतरी में 1,32,826.00 क्विंटल धान उपार्जित किया गया है। वहीं दरबा, मरौद, सबलपुर, नारी, भखारा और करेली केंद्रों में भी खरीदी कार्य सतत रूप से जारी है।

नवाचार केवल प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज से जोड़ना होगा: श्री डेका

रायपुर। नवाचार केवल प्रयोगशालाओं और कक्षाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे समाज से जोड़ना होगा। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज संस्थान नवाचार परिषद (आईआईसी) के क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उक्त बातें कहीं। इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया तकनीकी शिक्षा परिषद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आज शंकराचार्य व्यावसायिक प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल श्री डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री डेका ने कहा कि यह सम्मेलन न केवल इस संस्थान के लिए बल्कि हमारे राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय नवाचार यात्रा में छत्तीसगढ़ की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, पारंपरिक ज्ञान, हस्तशिल्प, कृषि, वनोपज और जनजातीय ज्ञान की भूमि है। सही रूप में किया गया नवाचार हमारी स्थानीय शक्तियों



का मूल्य संवर्धन करके उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने योग्य और आर्थिक व तकनीकी रूप से उन्नत बनाता है, इसमें हमारे युवाओं की महती भूमिका है। एक छोटा सा नवाचार मानव की बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है। संस्थान नवाचार परिषद के क्षेत्रीय सम्मेलन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन

श्री डेका ने कहा कि 21वीं सदी के विद्यार्थी सौभाग्यशाली हैं। इस सदी में इंटरनेट सबसे बड़ी खोज है। श्री डेका ने कहा कि सतत विकास आज की सबसे बड़ी जरूरत है और यह विज्ञान से ही संभव है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, माइक्रो प्लास्टिक और मधुमेह की बीमारी को वर्तमान की सबसे बड़ी

समस्या बताते हुए कहा कि युवा विद्यार्थी इस क्षेत्र में नवाचार कर इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, जिसेके लिए वे अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप भारत के भविष्य के पेशेवर और भविष्य निर्माता हैं। केवल लाभ पाने के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए नवाचार करें। अपने विचारों को वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ाएं। अस्पष्टता से न डरें क्योंकि हर अस्पष्टता आपको बेहतर प्राप्त करना सिखाती है। युवाओं का साहस, जिज्ञासा और प्रतिबद्धता वर्ष 2047 के भारत को परिभाषित करेगी और भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। कार्यक्रम में उपस्थित एआईसीटीई नई दिल्ली के उपनिदेशक डॉ. निखिल कांत ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। एसएसआईपीएमटी भिलाई के चेयरमैन श्री आई पी मिश्रा ने भी अपना संबोधन दिया।

बटन चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशानुसार व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल के मार्गदर्शन में लगातार अपराध व अपराधियों के अवैधानिक कुलों में अंकुश लगाने व उनके विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में दिनांक 02/12/2025 को थाना कोनी पुलिस को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घुटकु तालाब के पास रोड किनारे जय लोनिया नामक व्यक्ति अपने हाथ में लोहे का धारदार बटन चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका कर दहशत फैला रहा है कि सूचना तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु हमराह स्टफ,गवाह के रवाना होकर मुखबिर के बताये स्थान में जाकर घेराबंदी कर आमजनों को भयभीत करने वाले जय लोनिया को पकड़ा गया पुछताछ करने पर उसने अपना पूरा नाम पता जय लोनिया पिता होश राम लोनिया उम्र-19 वर्ष निवासी ग्राम घुटकु थाना कोनी जिला बिलासपुर का रहने वाला बताया जिससे गवाहों के समक्ष एक लोहे का धारदार बटन चाकू जिसकी कुल लम्बाई 09 इंच, बरामद किया गया।

कलेक्टर गाइडलाइन की अव्यावहारिक वृद्धि पर सांसद का प्रहार

जनभावनाओं का सम्मान ही लोकतंत्र का आधार सांसद बृजमोहन

जनता पर आर्थिक बोझ नहीं होने देगे: सांसद बृजमोहन का गाइडलाइन दरों में 100-800 प्रतिशत वृद्धि के खिलाफ CM को पत्र

रायपुर । छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता एवं रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर अपनी दृढ़, संवेदनशील और जननायक शैली का परिचय दिया है। प्रदेश में भूमि खरीदी-बिक्री के लिए कलेक्टर गाइडलाइन दरों में 100 से 800 प्रतिशत तक की वृद्धि पर आपत्ति जताते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को विस्तृत पत्र लिखकर इस निर्णय को तत्काल स्थगित कर पुनर्विचार करने की मांग की है। अपने पत्र में अग्रवाल ने लिखा है कि, प्रदेश में बिना किसी

जन-परामर्श, बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन और बिना सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की समीक्षा के कलेक्टर गाइड लाइन दरों में अनियोजित वृद्धि कर दी गई है। इससे पूरे प्रदेश में अनेक वर्गों में असंतोष उत्पन्न पर है। किसान, छोटे व्यवसायी, कुटीर-उद्यमी, मध्यम वर्ग, छोटे रियल एस्टेट क्षेत्र और निवेशक - सभी इस निर्णय के खिलाफ है व्यापक विरोध को देखते हुए यह निर्णय किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। सांसद अग्रवाल ने स्पष्ट कहा है कि यह वृद्धि “इज ऑफ़लिविंग” और “इज ऑफ़ड्रूंग बिजनेस” दोनों के विपरीत है और प्रदेश की आर्थिक रीढ़ पर सीधी चोट है। उन्होंने लाभांजी और निमोरा जैसे गाँवों के चौकाने वाले उदाहरण प्रस्तुत कर बताया कि किस प्रकार बिना किसी वास्तविक मूल्यांकन के गाइडलाइन दरों में 725% और 888% तक की वृद्धि कर दी गई है, जो किसी भी आर्थिक न्याय का पालन नहीं करती। साथ ही, नवा रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों को बिना आवश्यक सुविधाएँ विकसित किए नगरीय क्षेत्र घोषित

करने पर भी उन्होंने गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद अग्रवाल का कहना है कि, गाइड लाइन दर में वृद्धि पर दावा किया जा रहा है कि किसानों को भूमि अधिग्रहण में अधिक मुआवजा मिलेगा। परन्तु वस्तुस्थिति बिल्कुल अलग है। भूमि का केवल 1% हिस्सा ही अधिग्रहण में आता है, किंतु 99प्रतिशत जनता पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। गाइडलाइन मूल्य 100प्रतिशत बढ़ाने के बाद भी पंजीयन शुल्क 4प्रतिशत बनाए रखना जनता के साथ अन्याय है, जिसे घटाकर पुनः 0.8प्रतिशत किया जाना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि, 20/11/2025 को लागू नई गाइडलाइन वृद्धि को तत्काल स्थगित किया जाए। पूर्ववत् गाइडलाइन पुनः लागू की जाए साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर वास्तविक बाजार मूल्यांकन कराया जाए। श्री अग्रवाल ने नवा रायपुर में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र से करने तथा पंजीयन शुल्क 4प्रतिशत से घटाकर 0.8प्रतिशत किया जाए।

राजभवन में मनाया गया 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

रायपुर । राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में राजभवन में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डेका ने कहा कि राज्यों की विविधताओं को राष्ट्रीय एकता एक सूत्र में पिरोती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' अभियान इसी एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का सशक्त प्रतीक है। राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम् में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में राज्यपाल रमेन डेका ने कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तराखण्ड, लक्षद्वीप, और पुदुचेरी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के स्थापना दिवस के अवसर पर कहा कि भाषाओं, वेशभूषा, खान-पान, कला और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हमारी आत्मा एक है। यही विविधता भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है। केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में आज राजभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में इन राज्यों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राज्यपाल ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक ईकाई नहीं है बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का जीवंत संगम है। डेका ने विभिन्न राज्यों की विशेषताओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य प्राचीन विरासत और आधुनिक तकनीक का संगम है। बीते युग में विजय नगर साम्राज्य ने कला और स्थापत्य को ऊंचाई दी।

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हमें यह सिखाता है कि सक्षम समाज वही है जो सबको साथ लेकर चलता है – मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। छत्तीसगढ़ सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समाज को यह समझने का अवसर देता है कि दिव्यांगजन किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक सशक्त और प्रगतिशील समाज वही है जो सभी को बराबरी के अवसर प्रदान करे और किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण पीछे नहीं रहने दे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकार, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सहायता उपकरण, कौशल-विकास, रोजगार अवसर, सामाजिक

सुरक्षा और अनुकूल वातावरण निर्माण के लिए अनेक योजनाएँ सुदृढ़ रूप से लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में समान और सशक्त भागीदारी दिलाने का है, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ राज्य के विकास में सक्रिय योगदान दे सकें। मुख्यमंत्री ने समाज के सभी वर्गों से आह्वान किया कि दिव्यांगजनों के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाएँ और उनके साथ सम्मानजनक, सहयोगपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार अपनायें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन तभी वास्तविक रूप से सशक्त होंगे जब समाज और शासन मिलकर ऐसी परिस्थितियाँ तैयार करें, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुरूप आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस हमें समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का संदेश देता है।

‘पाञ्चजन्य कॉनक्लेव – दंतेश्वरी डायलॉग’ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने साझा किए

रायपुर। राजधानी नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिर्साईट में आयोजित पाञ्चजन्य कॉनक्लेव ‘दंतेश्वरी डायलॉग’ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल, बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्रों में विकास, नक्सल उन्मूलन, औद्योगिक निवेश, महिला सशक्तिकरण तथा नई टेक्नोलॉजी आधारित विकास मॉडल सहित अनेक विषयों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न सवालों के सरल और स्पष्ट उत्तर देकर सरकार की योजनाओं और आगामी रोडमैप की जानकारी दी।

महिला सशक्तिकरण सबसे बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि दो वर्षों में महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम बनी है।70 लाख महिलाओं को हर महीने



1000 रुपए की सम्मान राशि दी जा रही है, जिससे परिवारों में पोषण, बच्चों की शिक्षा और घरेलू जरूरतों में सकारात्मक बदलाव आया है।

टेक-ड्रिवन छत्तीसगढ़ डू नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में नई

उद्योग नीति लागू की गई है, जिसमें रोजगार को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही नई औद्योगिक नीति में निवेश को आकर्षित करने के लिए आकर्षक अनुदान,सिगल विंडो सिस्टम,250 से अधिक इंच ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को भी शामिल किया गया है। इसी का परिणाम है कि अभी तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में आईटी, एआई, ग्रीन टेक व सेमीकंडक्टर जैसी नई पीढ़ी की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया गया है।नवा रायपुर को आईटी हब, बस्तर का विकास स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और आधुनिक सुविधाओं के संतुलन के आधार पर होगा। कृषि, सिंचाई, जैविक खेती, वनोपज

प्रसंस्करण, पर्यटन और स्थानीय रोजगार पर विशेष फोकस किया जा रहा है। वनोपज संग्राहकों के लिए बेहतर सुविधा

प्रधानमंत्री वनधन योजना और वनोपज आधारित प्रसंस्करण के विस्तार से संग्राहकों की आय में वृद्धि हो रही है। नक्सलवाद के विरुद्ध 'सामाजिक मनोवैज्ञानिक मोड़'मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली जाकर नक्सल पीड़ितों द्वारा अपनी बात रखना ऐतिहासिक कदम है। इससे बस्तर के लोगों में बढ़ा आत्मविश्वास आया और देश के सामने माओवादी हिंसा का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ।मतांतरण पर सख्त कार्रवाई और सांस्कृतिक सुरक्षा पर जोरउन्होंने कहा कि प्रलोभन या दबाव से होने वाले मतांतरण रोकने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई हो रही है।इसके लिए विधानसभा में विधेयक लाने की भी तैयारी की जा

रही है।जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य व डिजिटल कनेक्टिविटी में तेजी से सुधारमुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर और सरगुजा में मोबाइल टावरों की स्थापना, स्कूलों का पुनः संचालन और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षा गुणवत्ता में तेजी से वृद्धि हुई है।नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वासि और सुविधाओं के विस्तारनिषेध नेछा नार योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, चष्ट्र कार्ड, बिजली, पानी, सड़क और अन्य सुविधाएँ तेजी से उपलब्ध कराई जा रही हैं।दो वर्षों में गारंटियों का सफल क्रियान्वयनमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित अधिकांश गारंटियाँ पूरी की जा चुकी हैं। इनमें 18 लाख आवास स्वीकृत,किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य,महतारी वंदन योजना,तंदूपता संग्राहकों की बढ़ी हुई राशि,भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता आदि शामिल है।

संपादकीय

रोहिंग्या देश के सुरक्षा के लिये खतरा

रोहिंग्या देश के सुरक्षा के लिये खतरा है जिस तरीके से घुसपैठ करने का कुचक्र किया जा रहा है वह चिंतनीय है। एसआईआर ने राज्यों की राजनीति को जिस तरह बदला है, वह केवल एक चुनावी मुद्दा नहीं रह गया है; यह पहचान, सुरक्षा और शासन की विश्वसनीयता से जुड़ा भावनात्मक प्रश्न बन चुका है। एक ओर इसी पृष्ठभूमि में यह सच्चाई भी सामने आने



ललित गर्ग

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

स्मृतियां,यादों का सफर		
स्मृतियां चुपचाप चलती पैरों की तरह नहीं, साँसों की तरह चलती ।	नीम के पेड़ आज भी उतने ही रहे, धूप पहले जैसी गर्म नहीं लगती । कभी दरवाजा खुलने की आवाज बिना दस्तक लौट आती , माँ रसोई से पुकारती हो खाना ठंडा हो रहा है ।	
यादें कंधों पर नहीं बैठतीं, मन के अंदर किसी पुरानी बेंच पर बैठ जाती स्कूल की छुट्टी में कोई बच्चा घर जाने की जल्दी में न हो ।	कुछ स्मृतियां काट की मेज पर रखे गिलास जैसी पारदर्शी, कुछ धुएँ जैसी जो पकड़ में नहीं आती, आँखें भिगो देती ।	यादों का यह सफ़र कहीं पहुँचने के लिए नहीं होता, यह लौटने के लिए होता उसी जगह जहाँ जीवन पहली बार मुस्कुराया ।
कभी पुरानी सड़क मिल जाती जिसके किनारे		स्मृतियां पुराने घर की दीवार नहीं, उसकी धड़कन होती जो कहती , समय बीत जाता, पर सच में कुछ भी बीतता नहीं ।
		– संजीव ठाकुर



PM : 2024 -
Vishwa Sarkar Ka Vikalp



QR CODE SCAN

कर प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा लिखित पुस्तकें पढ़िये ऑनलाईन



Modimaya
Vaidik_Netritva



Rashtriya Ekta

DLF-Vadra-
Bhrasht Tantra

Silent Assassins
Jan11,1966

Accursed & Jihadi
Neighbour

स्वाधीनता के संघर्ष, स्वाभिमान से उपजी भारत की एकता और अखंडता राष्ट्र सर्वोपरि

भारत की स्वतंत्रता अनगिनत बलिदानों, त्याग, तप और संघर्ष की अमूल्य विरासत है। लगभग आठ सौ से हजार वर्षों की परतंत्रता के बाद, जब विदेशी शासन की दासता से मुक्त होने के लिए लाखों भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर हमें स्वतंत्रता का वह अमृत प्राप्त हुआ जिसे हम आज खुले आकाश के नीचे निरंतर सांस लेते हुए अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान, साहस और एकता की अनुपम साधना का परिणाम है। इसलिए यह हमारा पवित्र दायित्व है कि हम इस स्वतंत्रता को, इस अखंडता को और इस राष्ट्रीय आत्मा को अनंतकाल तक अक्षुण्ण बनाए रखें। राष्ट्र की एकता केवल संविधान के पन्नों या शासन की व्यवस्था से सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि नागरिकों की चेतना, परस्पर सम्मान, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति की अंतर्मन की प्रतिज्ञा से निर्मित होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का स्वरूप और अधिक मजबूत हुआ, परंतु आज दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक मंसूखों, स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों और विचारधारात्मक विभाजन ने समाज में संप्रदाय, भाषा, जाति और क्षेत्र के नाम पर दरारें पैदा करने का प्रयास किया है।

मंदिर-मस्जिद, गुरुद्वारा-चर्च, हिंदी-अंग्रेजी-उर्दू-पंजाबी-तेलुगु-असमी जैसे विवाद हमारे हृदय में ऐसे ही घाव हैं जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए हमें सांप्रदायिक विद्वेष, ईर्ष्या, भाषाई और सीमाई विवादों से ऊपर उठकर सामाजिक सौहार्द, मानवीय गरिमा और राष्ट्र की समग्रता को प्राथमिकता देनी होगी, तभी हम विकास की मुख्यधारा में सार्थक योगदान दे पाएंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि «भारत विश्व का एकमात्र राष्ट्र है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों का सहअस्तित्व सर्वधर्मसमभाव के अद्वितीय स्वरूप में विद्यमान है।» यह कथन भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक चरित्र का आदर्श प्रतिबिंब है। परंतु वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आतंकवाद शांति, सद्भावना और किसी भी राष्ट्र की अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। कभी अमेरिका, तो कभी भारत के दिल्ली, मुंबई और अनेक राज्यों में आतंकवाद ने अपनी विभीषिका से भारी जनहानि और संपत्ति विनाश का अंधकार फैलाया है। इसके अतिरिक्त अलगाववादियों ने भी राष्ट्र की परंपरागत एकता और अखंडता को विखंडित करने का निरंतर प्रयास किया है। कुछ राजनीतिक शक्तियों ने वोट बैंक की राजनीति में उलझकर अलगाववाद और साम्प्रदायिकता का बीजारोपण किया है-कभी अल्पसंख्यकों के नाम पर विभाजन, कभी जाति और आरक्षण के नाम पर भ्रम और विद्वेष की स्थापना कर समाज को बांटने का

दुर्भावनापूर्ण प्रयास किया है। यह राजनीति का सबसे निंदनीय और चिंतनीय स्वरूप है, जिस पर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। वास्तविकता यह है कि सामान्य सामाजिक स्तर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य सभी वर्ग अत्यंत सौहार्द, सद्भावना और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। परंतु स्वार्थी तत्व इन संबंधों को तोड़कर समाज को संघर्ष और अविश्वास की आग में धकेल देते हैं। राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने की जिम्मेदारी मात्र राजनेताओं या प्रशासन पर नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से है। हमें यह दृढ़ संकल्प लेना होगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है-धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश या दल से बड़कर। यदि हम इतिहास के पन्नों को देखें तो अनेक आक्रमणों, विदेशी शासन और सांस्कृतिक संघर्षों के पश्चात भी भारत की मूल अस्मिता बार-बार सशक्त होकर उभरी है। यहाँ अनेकों जातियाँ और समुदाय आए, उन्होंने अपनी परंपराएँ, भाषाएँ और संस्कृति साथ लाईं, पर समय के साथ वे भारत की मुख्य धारा में समाहित होकर इस मिट्टी का अभिन्न अंग बन गये। यही भारत की सांस्कृतिक एकरूपता का वैश्विक चमत्कार है, जिसकी शक्ति आज भी अक्षुण्ण है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने

कर्म, विचार और संकल्प से भारत की अखंडता, स्वतंत्रता और गौरव को विश्व पटल पर और अधिक सुदृढ़ स्थापित करें। राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि तभी संभव है जब संचार माध्यम, मीडिया, साहित्यकार, कलाकार, युवा शक्ति और प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक अपने दायित्व को समझते हुए देश को सर्वोपरि रखें और विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हों। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत एकता के सूत्र में बंधा, वह विश्व में शक्ति बनकर उभरा; और जब भी विभाजित हुआ, वह कमजोर और असहाय सिद्ध हुआ। अतः यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की अस्मिता को किसी भी मूल्य पर खंडित न होने दें। हम सबको आज उसी भावना से उठना होगा, जिससे- «भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, वह हमारी आत्मा है, हमारी संस्कृति है, हमारा गौरव है।» आइए आज संकल्प लें-हम एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक पहचान और एक संकल्प के साथ भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता को अनंत काल तक बनाए रखेंगे। राष्ट्र सर्वोपरि-हम सबका प्रथम धर्म। यह निजी विचार है।

(संपादकीय + संदेश)

नए भारत को सुरक्षा एवं संवेदना वाली नई पुलिस चाहिए

ललित गर्ग
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार

भारतीय लोकतंत्र में पुलिस व्यवस्था कानून-व्यवस्था की आधारभूत धुरी है, परंतु आम नागरिक के मानस में पुलिस की छवि अभी भी कठोरता, डर और दमन से जुड़ी हुई है। इसे केवल अधिकार जताने वाली शक्ति समझा गया है, संवेदनशीलता, जवाबदेही और मित्र भाव से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में इसी जटिलता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुलिस की छवि तभी बदलेगी जब व्यवस्था अधिक प्रोफेशनल, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवीय बने। विकसित भारत की दृष्टि में पुलिस का पुनर्गठन केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि समाज में भरोसे को पुनर्जीवित करने का कार्य भी है। पुलिस के पास अपराध नियंत्रण, आतंकवाद-निरोध, भीड़ प्रबंधन, आपदा राहत, नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान, चुनाव ड्यूटी और वीआईपी सुरक्षा जैसी असंख्य जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं, कार्य-भार भारी और राजनीतिक दबाव व्यापक है। कुछ अधिकारियों के भ्रष्ट या कठोर व्यवहार ने संपूर्ण पुलिस व्यवस्था की छवि पर चोट पहुँचाई है, इसलिए जनता पुलिस के निकट आने पर भी भय का अनुभव करती है। प्रधानमंत्री ने इस स्थिति बदलने की स्पष्ट आवश्यकता जताई और युवाओं में पुलिस की सकारात्मक छवि निर्माण पर बल दिया ताकि आने वाली पीढ़ी पुलिस को मित्र और संरक्षणकर्ता के रूप में पहचाने।

भारतीय लोकतंत्र के संरचनात्मक स्तंभों में पुलिस की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। वह केवल अपराधियों से मुकाबला करने वाली शक्ति नहीं बल्कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता और जनविश्वास की संरक्षक है। परंतु विडम्बना यह है कि आम जनता के मानस में पुलिस की छवि आज भी कठोरता, डर, भ्रष्टाचार और दमन से जुड़ी हुई दिखाई देती है। समाज पुलिस को «डंडे» और «खाकी» के प्रतीक रूप में पहचानता है, संवेदनशीलता और जवाबदेही के दृष्टिकोण से नहीं। यही कारण है कि पुलिस सुधार दशकों से विमर्श का विषय तो रहा, लेकिन कभी जनांदोलन नहीं बन सका, न चुनावी मुद्दा बना और न ही गंभीर राजनीतिक प्राथमिकता। इसलिये मोदी ने शहरी पुलिसिंग को मजबूत करने, पर्यटक पुलिस को फिर से सक्रिय करने, विश्वविद्यालयों को पेरिसिक अध्ययन के लिए प्रेरित करने और नए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा नागरिक सुरक्षा संहिता पर व्यापक जनजागरूकता चलाने की जरूरत रेखांकित की। उनका यह दृष्टिकोण पुलिस को प्रतिक्रियाशील संस्था से आगे बढ़ाकर बुद्धिमान, वैज्ञानिक, पूर्वानुमान आधारित और विश्वसनीय संस्था बनाने की दिशा है।

प्रधानमंत्री की दृष्टि का महत्वपूर्ण आयाम यह है कि पुलिस केवल कानून लागू करने वाली मशीन नहीं बल्कि समाज का सहभागी तंत्र है। यदि पुलिस व्यवहार में संवेदनशीलता, संवाद, पारदर्शिता और विनम्रता विकसित करे तो जनविश्वास स्वतः बढ़ेगा। नए कानूनों के बारे में जन-जागरूकता अभियान इसी सोच का हिस्सा है, क्योंकि

कानून तभी प्रभावी होते हैं जब जनता उन्हें समझती और स्वीकार करती है। अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए पुलिस का प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता, इंटेलिजेंस नेटवर्क और पेरिसिक क्षमता मजबूत होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री ने नेटग्रिड, ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एकीकृत डेटाबेस के प्रभावी उपयोग पर जोर देकर पुलिसिंग को डेटा आधारित, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-एआई और वैज्ञानिक सोच से जोड़ने की दिशा दिखाई है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठनों की सतत निगरानी, नशीली दवाओं के विरुद्ध बहुस्तरीय रणनीति, कट्टरपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में विकास आधारित समाधान, तटीय सुरक्षा के नवाचार, तथा प्राकृतिक आपदाओं में सक्रिय पुलिस नेतृत्व की आवश्यकता भी व्यक्त की। यह सब उस व्यापक सोच का हिस्सा है जिसमें पुलिस केवल अपराध से लड़ने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि विकास की रणनीतिक सहभागी शक्ति है।

परंतु पुलिस सुधार केवल निर्देशों से संभव नहीं; इसके लिए संतुलित एवं अत्याधुनिक ढांचे की जरूरत है जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन, मनोबल, आचार-नीति, राजनीतिक निभरताओं से मुक्ति और सामाजिक सम्मान शामिल हों। आलोचना जितनी महत्वपूर्ण है, पुलिस के संघर्षों को समझना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि इसी दौराफ समझ से सुधार का रास्ता निकलता है। प्रधानमंत्री की अपेक्षा है कि पुलिस नेतृत्व खुद को नए भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तैयार करे, लक्ष्य स्पष्ट करे और वह व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिक पुलिस को भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखें। विकसित भारत की यात्रा में सुरक्षा, न्यायबोध और अनुशासन की संरचना को सशक्त बनाने के लिए पुलिस का आधुनिक, मानवीय और विश्वसनीय स्वरूप अनिवार्य है। यह सुधार केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि सोच, दृष्टि और चरित्र का परिवर्तन है। तभी खाकी का सम्मान लौटेगा, जनता का विश्वास मजबूत होगा और पुलिस व्यवस्था वास्तव में लोकतंत्र की प्रहरी के रूप में पहचानी जाएगी।

प्रधानमंत्री के ताजा विचारों ने स्पष्ट किया है कि पुलिस की छवि सुधारने का अर्थ केवल कठोरता घटाना नहीं, बल्कि उसे प्रोफेशनल, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। आज जरूरत इस बात की है कि पुलिस व्यवस्था के लिए भय का नहीं, विश्वास और सुरक्षा का केंद्र बने। शहरी पुलिसिंग को सुदृढ़ करने, पर्यटक पुलिस को पुनर्जीवित करने और नए आपराधिक कानूनों पर जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि इससे पुलिस «डंडे की ताकत» से आगे बढ़कर «मदद की शक्ति» बनेगी। यदि नागरिक को यह अनुभव होने लगे कि पुलिस मदद के लिए तत्पर है, उसके अधिकारों का सम्मान करती है और कानून का निष्पक्ष पालन करती है, तो खाकी वर्दी का अर्थ केवल अनुशासन नहीं बल्कि विश्वास, अभय और सहारा प्रतीत होगा। यही वह परिवर्तन है जो

विकसित भारत की सोच में निहित है। अंग्रेजी शासकों ने अपने शासन को थोपने, जनता को नियंत्रित करने और भय-आधारित प्रशासन चलाने हेतु पुलिस तंत्र की रचना की। 1860 के कानून के आधार पर स्थापित भारतीय पुलिस का मूल चरित्र दंडात्मक, शासक-केन्द्रित और कठोर शक्ति-प्रयोग वाला था। स्वतंत्रता के बाद भी इस व्यवस्था में सार्थक बदलाव न होना एक विडंबना है। आज़ाद भारत ने लोकतंत्र अपनाया पर पुलिस ढांचे ने अभी तक औपनिवेशिक सोच को पूरी तरह त्यागा नहीं। परिणामतः पुलिस जनसेवा की बजाय सत्ता को बचाने और भय पैदा करने का उपकरण बनी रह गई। आज आवश्यकता है कि भारत का पुलिस तंत्र भारत के मूल्यों के अनुरूप पुनर्निर्मित हो। विकसित भारत को विकसित सोच वाली पुलिस चाहिए जो नागरिकों के साथ विश्वास-आधारित संबंध बनाए, दमन नहीं बल्कि संरक्षण दे, और कानून को लागू करने में नैतिकता, पारदर्शिता और मानवता को प्राथमिकता दे। ऐसी पुलिस व्यवस्था ही सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की प्रहरी बन सकती है और भारत की सभ्यता-संस्कारों का प्रतिबिंब भी।

इसी संदर्भ में पुलिस थानों के नामकरण की सोच पर पुनर्विचार भी आवश्यक है। «थाना» शब्द में दमन और भय की छया रही है, जबकि लोकतांत्रिक समाज में वह नागरिक सहारा का स्थान होना चाहिए। यदि उन्हें «सुरक्षा केंद्र», «नागरिक सहायता केंद्र», «पुलिस सेवा भवन», «अभय केंद्र» या «सहयोग प्रहरी केंद्र» जैसे नाम दिए जाएं तो नागरिक के मानस में पुलिस की भूमिका का अर्थ बदलने लगेगा। नाम केवल शब्द नहीं होता, वह भाव, चरित्र और अनुभव निर्मित करता है। इस सकारात्मक नामकरण से पुलिस केन्द्र केवल लश्करी या धमकाने का प्रतीक नहीं बल्कि सहायता, समस्या-समाधान, विश्वास और न्याय का केन्द्र बन सकता है। यह प्रतीकात्मक परिवर्तन, यदि व्यवहार सुधार के साथ जुड़ जाए, तो पुलिस के प्रति जनता में सम्मान, निष्ठा और आसुरेदारी की भावना और अधिक मजबूत होगी और यही वह दिशा है जिसे विकसित भारत की सुरक्षा, नीतिगत सोच और संवेदनशील शासन का स्वरूप कह सकते हैं।

इसके विपरीत आज की वास्तविकता यह है कि जब पुलिस दरवाजे पर आती है, तो नागरिक घबराता है-«कहीं फंस न जाऊं।» यह भय उस विश्वासहीनता का परिणाम है जिसे बदलना आवश्यक है। अपराध की प्रकृति बदल रही है, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, आतंकवाद, मानव तस्करी, ड्रग नेटवर्क-इन्से मुकाबले के लिए बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक और इंटे्लिजेंस चाहिए। लोकतंत्र में पुलिस सबसे प्रत्यक्ष शासन-कर्म है। जनता रोज उसे देखती, झेलती और समझती है। खराब अनुभव सीधे शासन के प्रति अविश्वास पैदा करते हैं। विकसित भारत 2047 की आकांक्षाओं में पुलिस वह संरचना है जो सुरक्षा, अनुशासन, न्याय और सामाजिक साझेदारी को सुनिश्चित करती है। पुलिस की वर्दी के भीतर मनुष्य, संवेदना और विवेक दिखाई दे, तभी खाकी का सम्मान लौटेगा और जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा। नए भारत के निर्माण में पुलिस का यह रूपांतरण एक निर्णायक धुरी होगा, जहाँ सुरक्षा और संवेदनशीलता साथ-साथ चले, और जहाँ कानून केवल भय नहीं बल्कि न्याय और विश्वास का प्रतीक बने।

कांग्रेस का एकमात्र मकसद सत्ता घस करना

बलवीर गुंज

कांग्रेस कभी औपनिवेशिक विभाजनकारी नीतियों से लड़ने का प्रतीक थी। किंतु दुर्भाग्य से, वही विषाक्त चिंतन पं.नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के दौर से गुजरते हुए आज राहुल गांधी के समय तक पार्टी की नस-नस में समा गया है। अब कांग्रेस नेतृत्व का एकमात्र मकसद किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना रह गया है- चाहे इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा-अखंडता को दांव पर लगाकर भारत की प्रतिष्ठा को ही धूमिल क्यों न करनी पड़े।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस को मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस कहने और उसे देश के लिए खतरा बताने का निहितार्थ क्या है? इस विचार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार नहीं, बल्कि तीन अवसरों पर व्यक्त किया है। पहले 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत राजग गठबंधन द्वारा दर्ज प्रचंड जीत पर दिल्ली में भाजपा समर्थकों को संबोधित करते हुए। फिर 15 नवंबर को गुजरात स्थित सूरत के एक कार्यक्रम में और इसके बाद 17 नवंबर को दिल्ली में आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान में।

प्रधानमंत्री के मुताबिक, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन-नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, अब वो कांग्रेस को 'मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस' (एम.सी.सी.) बना चुके हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मुस्लिम-लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश के लिए खतरा बनते जा रही है। कांग्रेस की यह छवि एकाएक नहीं बनी है और न ही यह मात्र कोई चुनावी या राजनीतिक जुमलेबाजी है।

कांग्रेस का संकट बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे पर उसके आधिकारिक वक्तव्य से स्पष्ट है, जिसमें पार्टी नेतृत्व मतदाता द्वारा नकारे जाने को फर्जी वोट चोरी का परिणाम बता रही है। दरअसल, वर्तमान कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता-विपक्ष राहुल गांधी जिस विभाजनकारी मार्ग पर चल रहे है, उसकी प्रेरणा उन्हें अपने परिवार ही से मिली है। वर्ष 1950 से राहुल के परनामा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस विकृत सेकुलरवाद को अपनाया, उसने देश में इस्लामी कट्टरता और हिंदू-विरोधी शक्तियों को नया जीवनदान दिया।

पहले उन्होंने जम्मू-कश्मीर के इस्लामी स्वरूप को बरकरार रखने हेतु अनुच्छेद 370-35ए को संविधान में बिना चर्चा के 'चोर दरवाजे' से शामिल करवाया, तो बहुसंख्यकों के लिए 'हिंदू कोड बिल' लागू करके मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर मुस्लिम समाज को हलाला और तीन तलाक जैसी कुतियायों के साथ छोड़ दिया। पं.नेहरू के लिए हिंदू मंदिर दमनकारी, तो केवल हिंदू ही सांप्रदायिक थे। कालांतर में उनके द्वारा अपनाई समाजवाद प्रेरित नीतियों ने भारतीय आर्थिकी को ध्वस्त कर दिया, जिसकी चर्चा पिछले कुछ लेखों में की जा चुकी है।

यह विकृति राहुल की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन में और बढ़ गई। उन्होंने 1969 में कांग्रेस टूटने के बाद अपने धड़े की वैचारिक संगोष्ठी उन वामपंथियों के हाथों में सौंप दी, जो अधिनायकवाद को बढ़ावा देने के साथ न तो तब स्वयं को भारत की बहुलतावादी सनातन संस्कृति से जोड़ पाए थे, न ही अब जोड़ पाते है। इसके परिणामस्वरूप, अदालत द्वारा अपनी वोट चोरी पकड़े जाने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल (1975-77) थोप दिया। इसी दौरान अयोध्या में भारतीय पुरातत्व विभाग की श्रीरामजन्मभूमि मंदिर के प्रमाण संबंधित उत्खनन रिपोर्ट को किसी भी दबा दिया गया। कालांतर में पंजाब में अपनी विरोधी अकाली दल को हाशिए पर पहुंचाने हेतु उन्होंने मृत 'खालिस्तान' विचार को अपने क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता हथियाने की लातसा में पुनर्जीवित कर दिया। इसका उल्लेख गैर-राजनीतिक, पूर्व आईपीएस अधिकारी और भारतीय खुफिया एजेंसी 'रिसर्च एंड एनालिसिस विंग' (रॉ) में वर्षों जुड़े रहने के बाद सेवानिवृत्त हुए गुरुबख्श सिंह सिधू ने अपनी पुस्तक 'द खालिस्तान कांस्पीरेसी' में किया है। जैसे 1980 के दशक में जरनैल भिंडरवाले को आगे रखकर इंदिरा गांधी ने हिंदू-सिख संबंधों को लेकर आत्मघाती राजनीति की, ठीक उसी तरह राहुल के पिता राजीव गांधी ने वर्ष 1986 के शाहबानो मामले से 'मुस्लिम वोटबैंक' का बिगुल फूंक दिया। तब मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेकते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में प्रचंड बहुमत के बल पर मुस्लिम महिला उ्थान की दिशा में आए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया था। यह निजी विचार है।

CMYK

CMYK

इसरो के सफल अत्यंत दुर्गम स्थिति पैराशूट परीक्षण ने गगनयान के लिए सुदृढ़ मिशन सुरक्षा मानक स्थापित किए

डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद को आश्चस्त किया: सभी परीक्षण परिणाम अंतरिक्ष यात्रियों की आपातकालीन स्थिति और बचाव प्रशिक्षण में शामिल किए जाएंगे

पीआईबी

केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज संसद को बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो द्वारा हाल में एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप का सफल परीक्षण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, गगनयान, के लिए मिशन-तैयारी योजना को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह परीक्षण, अंतरिक्ष यान चालक दल के पैराशूट-आधारित मंदन प्रणाली के योग्यता अभियान का महत्वपूर्ण घटक है, जो इस

मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। डॉ. सिंह ने बताया कि नवीनतम एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप में सबसे चरम अवतरण स्थितियों में से एक का अनुकरण किया गया और दो मुख्य पैराशूटों के बीच डिसरीपिंग क्रम में जानबूझकर समय का अंतर रखा गया। इसमें असममित बलों के तहत प्रणाली की संरचनात्मक जुड़ाव और भार वहन क्षमता, दोनों की पुष्टि हुई। श्री सिंह ने कहा कि यह सफल परीक्षण मानव-योग्यता निर्धारण प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाता है और 2027 की पहली तिमाही तक पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन प्रक्षेपित करने के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है। संसद में प्रश्नकाल के दौरान तृतीय-पक्ष सत्यापन और तकनीकी निगरानी पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में डॉ. सिंह ने कहा कि इसरो नियमित रूप से कर्नू मॉड्यूल पैराशूट प्रणाली



और उससे संबंधित सभी परीक्षण परिणामों की स्वतंत्र और कठोर समीक्षा करता है। इनमें डिजाइन समीक्षा दल, स्वतंत्र मूल्यांकन समिति और मानव योग्यता निर्धारण एवं प्रमाणन के लिए देश भर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों

वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये संस्थागत मंच सभी मानव-मूल्यांकन तत्वों की गहन जांच करते हैं। पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों पर श्री सिंह ने

कहा कि इसरो निरंतर और समय-समय पर प्रमुख परीक्षण परिणामों की जानकारी देता रहता है, जिसमें हाल ही किये गए आई.एम.ए.टी. के परिणाम भी शामिल हैं। वह आगे भी कार्यक्रम की प्रगति के बारे में सूचित करना जारी रखेगा। यान चालक दल की तैयारियों से संबंधित मुद्दों पर, डॉ. सिंह ने दोहराया कि गगनयान मिशन के लिए उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रणालियों का गहन परीक्षण और विशेषज्ञ समीक्षा की जाती है, और प्रत्येक योग्यता परीक्षण के परिणामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर प्रणाली में सुधार किया जाता है। इसके बाद फिर उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण में आपातकालीन परिदृश्यों का व्यापक अनुकरण, ऑफनॉमिनल लैंडिंग की उत्तरजीविता प्रक्रियाएं, आपातकालीन किट

का संचालन और गगनयात्रियों की समग्र तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श शामिल है। श्री सिंह ने सदन को यह भी बताया कि इसरो ने स्थापित वैश्विक मानकों के अनुरूप सुदृढ़ जोखिम-मूल्यांकन और न्यूनीकरण ढाँचे को संस्थागत रूप दिया है। मानव मूल्यांकन प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय सलाहकार पैनल जैसी संस्थाएं इन प्रक्रियाओं की निगरानी करती हैं ताकि सुनिश्चित हो कि समग्र मिशन के दौरान जोखिम नियंत्रण में रहे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि हाल के आईएमएटी सहित प्रत्येक परीक्षण का महत्वपूर्ण प्रणालियों को मान्य बनाने के साथ ही चालक दल के प्रशिक्षण, ग्राउंड रिकवरी तैयारियों और भारत के ऐतिहासिक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के सुरक्षित निष्पान में योगदान है।

ट्राई ने असम लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (एलएसए) के अंतर्गत असम राज्य के बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों में नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

पीआईबी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अक्टूबर 2025 में बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों के व्यापक शहर मार्गों को कवर करते हुए असम एलएसए के लिए अपने स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के नतीजे जारी किए। ट्राई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय की निगरानी में किए गए इन ड्राइव टेस्टों का उद्देश्य विभिन्न उपयोग परिवेशों - जैसे शहरी क्षेत्रों, संस्थागत हॉटस्पॉट, व्यावसायिक क्षेत्रों, ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों आदि - में वास्तविक मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन को दर्ज करना था। 28 अक्टूबर 2025 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच, ट्राई की टीमों ने असम राज्य के बारपेटा और बोंगाईगांव जिलों में विस्तृत परीक्षण किए, जिसमें 230.8 किलोमीटर का सिटी ड्राइव टेस्ट, 8 हॉटस्पॉट लोकेशन और 1.1 किलोमीटर का वॉक-टेस्ट शामिल था। मूल्यांकन की गई तकनीकों में 2व, 3व, 4व और 5व शामिल थे, जो विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव को दर्शाते हैं।

स्थानीय विकास में कोयला खदानों का योगदान

पीआईबी

झारखंड के मगध और आम्पाली खदानें मिलकर 2024-25 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की कुल कोयला उत्पादन का लगभग 50% योगदान देती हैं, इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप विद्युत उत्पादन के लिए सुनिश्चित कोयला आपूर्ति के राष्ट्रीय उद्देश्य का समर्थन करती हैं। मगध और आम्पाली कोयला खदानों के अनुमानित खनिज भंडार क्रमशः 854.91 मिलियन टन और 456.34 मिलियन टन हैं और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इनसे क्रमशः 2,812 करोड़ रुपये और 2,367 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री आय उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये खदानें परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी ए पी) और नजदीकी ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका सहायता प्रदान करके स्थानीय विकास में योगदान देती हैं। मगध-संघमित्रा क्षेत्र में 808 और आम्पाली-चन्द्रगुप्त क्षेत्र में 210 व्यक्तियों को रोजगार देने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। नमचिक नामपुक कोयला खदान अरुणाचल प्रदेश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देगी, क्योंकि यह प्रति वर्ष 0.2 मिलियन टन (एम टी पी ए) कोयले का योगदान करेगी। यह नियमित आपूर्ति राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को अधिक विश्वसनीय रूप से पूरा करने में मदद करेगी। इस खदान में अनुमानित भौगोलिक भंडार 14.97 एमटी हैं और यह लगभग 270 लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ सालाना 173 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करेगी। मिशन ग्रीन (प्रकृति को बढ़ाना, पुनर्स्थापित करना, समृद्ध करना और सशक्त बनाना) के तहत, कोयला क्षेत्र, कोयला और लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) ने, अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी

खास खबर

पंकज जायसवाल निधन

कोरबा, प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ उमाशंकर जायसवाल के ज्येष्ठ पुत्र पंकज जायसवाल का आज शाम साढ़े चार बजे निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। जायसवाल परिवार में शोक की लहर व्याप्त है।

पंकज अत्यंत मृदुभाषी और काफ़ी व्यवहार कुशल थे और समाज सेवा के क्षेत्र में भी सदैव आगे रहे।

रूमगरा हवाई पट्टी में जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक ने किया अभिवादन

कोरबा ,मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और वित्त मंत्री ओ पी चैधरी आज उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के कोहड़िया स्थित निवास पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री श्री देवांगन के भाई श्री कीशल देवांगन के सुपुत्र श्री विश्वेश देवांगन और मेघा देवांगन के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रूमगरा हवाई पट्टी पर हेलीकॉप्टर से उतरने के पश्चात जिलाधीश अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, कोरबा महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, डीएफओ श्रीमती प्रेमलता यादव, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय सहित अन्य अधिकारियों ने भी उनका आत्मीय स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से उतरने के पश्चात सभी अतिथि कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो गए।

जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर के नए अध्यक्ष बने मुकेश राठौर, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

कोरबा , जिला कांग्रेस कमेटी कोरबा शहर के अध्यक्ष पद पर मुकेश राठौर की नियुक्ति के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनके चयन का स्वागत करते हुए बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुकेश राठौर को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद कांग्रेसजनों में नए उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा तथा जनसंपर्क और निर्र्हत के कार्यों में नई गति आएगी। स्थानीय नेताओं ने भी उनके अनुभव, संगठन क्षमता और सक्रिय भूमिका की सराहना करते हुए बताया कि राठौर के आने से शहर कांग्रेस को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों ने उन्हें हार्दिक बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की है।

शिक्षिका ने शादी से किया इनकार, बारात में शराब पीकर पहुंचा था दूरस्थ

बिलासपुर ओडिशा के निजी स्कूल में शिक्षिका ने प्रेम विवाह के लिए परिवारवालों को मना लिया। जब दुल्हन तय समय पर बायात लेकर पहुंचा तो वह शराब के नशे में धुत था। उसकी हस्तों को देखकर युवती ने शादी से इन्कार कर दिया। इसके बाद युवक अब युवती के परिवारवालों को फोन पर धमकी दे रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। सखंडख क्षेत्र में रहने वाली युवती ओडिशा के निजी स्कूल में शिक्षिका है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह ओडिशा के बंधबाहाल में रहने वाले किशन से प्रेम करती थी। उसने अपने परिवारवालों को किशन से विवाह करने के लिए राजी कर लिया।

जल संरक्षण और कृषि नवाचार का संदेश, कृषि विशेषज्ञों ने दिए नवाचारपूर्ण सुझाव

नगपुरा में मनाया गया वाटरशेड महोत्सव

बिलासपुर (संवाददाता)। भूमि संसाधन एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छ.ग. राज्य में बिलासपुर जिले के कृषि विभाग में संचालित केन्द्रीय योजना डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0/1 द्वारा कोटा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत नगपुरा में वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया। माइक्रोवाटरशेड ग्राम नगपुरा में विविध आयोजना के तहत प्रभात फेरी, रंगोली एवं कबड्डी प्रतियोगिता, भूमि पूजन, श्रम दान एवं सरसों बीज का वितरण किया गया। वाटरशेड कमेटी नगपुरा में श्रमदान एवं निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इसके पश्चात् प्राथमिक शाला माइक्रोवाटरशेड नगपुरा के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी, पानी की पाठशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया गया। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जनपद पंचायत सदस्य परमेश्वर खुसरो मौजूद थे। इसके अलावा सरपंच ग्राम पंचायत नगपुरा श्रीमति अनुषा पैकरा, सरपंच ग्राम पंचायत तुलुफ मोहन सिंह श्याम, भूतपूर्व जनपद पंचायत सदस्य श्रीमति सुरति परमेश्वर खुसरो एवं विभागों से कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीमति डॉ. शिल्पा कौशिक, श्रीमति डॉ. एकता ताम्रकार एवं इंजीनियर पंकज मिंज, आईएफएमसीओ के प्रबंधक नवीन तिवारी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रबंधक अवनीश सिंह, परियोजना

महिला एवं बाल विकास मंत्री राजवाड़े ने किया बाल सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण

कोरबा संवाददाता। महिला एवं बाल विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े एवं छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती वर्णिका शर्मा ने कोरबा जिले में संचालित बाल संप्रेषण गृह (बालक), बाल गृह (बालिका) एवं बाल गृह (बालक) का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े और अध्यक्ष श्रीमती शर्मा ने बच्चों से संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं, उपलब्ध सुविधाओं और देखभाल की स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने संस्थाओं में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाए रखने के निर्देश देते हुए बच्चों के रहने, खाने, स्वास्थ्य, शिक्षा और देखभाल से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को पूर्णतः मानक अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु संस्था अधीक्षक एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। अधिनियम अंतर्गत तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड, पंजी और शासन द्वारा जारी निर्देशों को अद्यतन

रखने पर विशेष जोर दिया गया, ताकि बच्चों से संबंधित सभी प्रक्रियाएँ नियमों के अनुरूप संचालित हो सकें। मंत्री एवं अध्यक्ष द्वारा सभी संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त उपलब्धता और उनका सुचारु रूप से क्रियाशील रहना सुनिश्चित किया जाए, साथ ही प्रशिक्षित सुरक्षा गार्डों की उचित तैनाती भी आवश्यक है। संस्थाओं के प्रवेश-द्वारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों की नियमित निगरानी को भी अनिवार्य बताया गया, ताकि बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रहे। निरीक्षण के दौरान मंत्री एवं अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों की सुरक्षा, देखभाल, अधिकार संरक्षण एवं पुनर्वास से संबंधित सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के लिए सुरक्षित, संवेदनशील और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसे समयबद्ध रूप से पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसन्त और डीपीओ श्री बसंत मिंज भी उपस्थित थे।



कुसमुंडा में भविष्यपति महिलाओं का फूटा गुस्सा: एसईसीएल व जिला प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ मुख्य गेट पर ताला, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

कोरबा संवाददाता। कुसमुंडा क्षेत्र से प्रभावित भूविस्थापित महिलाओं का 22 वर्षों से जारी संघर्ष आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की कथित उदासीनता और संवेदनहीनता से नाराज महिलाओं ने सोमवार अलसुबह कुसमुंडा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के दोनों प्रवेश द्वारों पर ताला जड़ दिया। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के कारण उत्पन्न किसी भी अप्रिय स्थिति और कोयला उत्पादन में रुकावट के लिए पूरी जिम्मेदारी एसईसीएल और जिला प्रशासन की होगी।

22 वर्षों से जारी है न्याय की लड़ाई

कुसमुंडा परियोजना से विस्थापित महिलाएं रोजगार, बसाहट, पुनर्वास और लंबित समस्याओं के समाधान के लिए करीब दो दशक से अधिक समय से संघर्षरत हैं। आज के आंदोलन में गोमती, केवट, काजल, इन्द्रा, सरिता टिकैतराम बिंझवार, पूनम और मीना कंवर सहित कई महिलाएं शामिल रही। महिलाओं ने साफकहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, वे अनिश्चितकालीन धरने से नहीं हटेंगी और मुख्य गेट बंद ही रखेंगे।

वाद खिलाफी से बढ़ा आक्रोश

महिलाओं ने बताया कि बीते 17 नवंबर 2025 को भी उन्होंने कुसमुंडा कार्यालय में गेट जाम आंदोलन किया था। उस समय दरी तहसीलदार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि 21 नवंबर को बैठक कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन बैठक आयोजित नहीं हुई और आश्वासन एक बार फिर झूठा साबित हुआ। इसी वादाखिलाफी ने महिलाओं के गुस्से को और भड़का दिया।

एबीवीटीपीएस से सेवानिवृत्त हुए दो कर्मचारियों को दी गई भावपूर्ण विदाई

लोकशक्ति कोरबा-जांजगीर । अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह (एबीवीटीपीएस) मड़वा से नवंबर माह में वरिष्ठ पर्यवेक्षक रमेश कुमार गोपाल एवं हेमलाल ठाकुरसेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्तहो रहे दोनों कर्मचारियोंको पाँवर कंपनी परिवार की ओर से भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अभियंता एचएन. कोसरिया द्वारा उनके कार्यों की सराहना करते हुए पाँवर कंपनी की ओर से आभार जताया गया।मुख्य अभियंता के हाथों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृतिचिन्ह व सेवा प्रमाण-पत्र भेंट किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य अभियंता आलोक लकरा, एसडी. द्विवेदी, आरएल. ध्रुव, आरके. साव और एन. लकरा की गरिमामयी उपस्थिति रही। तकनीकी भवन के सभाकक्ष में आयोजित दीर्घ सेवा सम्मान समारोह



शुभकामनाएं दी गईं। रमेश कुमार गोपाल ने विद्युत मंडल एवं पाँवर कंपनी में 39 वर्ष 1 माह व 19 दिन की सेवाएं दी हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति कोरबा पश्चिम में संयंत्र परिचारक श्रेणी-तीन के पद पर हुई थी।जबकि हेमलाल ठाकुर ने 41वर्ष 3 माह व 10दिन की लंबी सेवाएं दी हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति कोरबा पूर्व में संयंत्र परिचारक श्रेणी-तीन के पद पर हुई थी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्मचारियोंद्वारा अपने दीर्घ कार्यकाल के अनुभवों को साझा किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए कल्याण अधिकारी आएएस. टेकाम द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियोंका सक्षिप्त जीवन परिचय का उल्लेख किया गया।कार्यक्रम में रामनारायण राठौर एवं विजय कुमार मिश्रा का विशेष सहयोग रहा।

जिले में मारपीट और तोड़फोड़ की दो अलग-अलग घटनाएं, वैभव होम्स में 18 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर, छात्रों की सड़क पर मारपीट

कोरबा एजेंसी। जिले में गत शुक्रवार रात दो अलग-अलग घटनाओं ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना मानिकपुर चैकी क्षेत्र के मुड़ापार शारदा विहार स्थित वैभव होम्स परिसर की है, जहां 29 नवंबर को लॉरी ने कॉलोनी में खड़ी करीब 18 गाड़ियों के शीशे तोड़कर उत्पात मचाया। दूसरी घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां स्कूली छात्रों के दो गुटों के बीच सड़क पर मारपीट होती देखी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वैभव होम्स में देर रात उत्पात, 18 गाड़ियों में तोड़फोड़ कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि रात करीब डेढ़ बजे एक युवक रॉड लेकर परिसर में घुसा और एक के बाद एक सभी गाड़ियों के शीशे तोड़ता चला गया। आवाज सुनकर जब लोग बाहर आए तो वह पीछे के रास्ते से भाग निकला। आश्चर्यजनक रूप से, आरोपी अगली सुबह फिर



कॉलोनी में आया और दोबारा उत्पात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की मौजूदगी देखकर फरार हो गया। वैभव होम्स परिसर के अध्यक्ष संदीप पांडे ने कहा कि घटना की सूचना रात में ही मानिकपुर चैकी पुलिस को दी गई थी और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मानिकपुर चैकी में पदस्थ एसएसआई अमर जायसवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम दीपू भारती है, जो एसईसीएल में सुरक्षकर्म है। वह चिरमिरी से कोरबा स्थानांतरित होकर दादर में किराए के मकान में रहता है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने टीपी नगर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी उत्पात मचाया था। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।



अधिकारी डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0/1 कोटा, डब्ल्यूसीडीसी, समस्त डब्ल्यूडीटी, वाटरशेड कमेटी के समस्त अध्यक्ष एवं सचिव मौके पर उपस्थित रहे। कृषि विज्ञान केन्द्र के विषय वस्तु विशेषज्ञ श्रीमति डॉ. शिल्पा कौशिक द्वारा ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन-तिलहन की खेती, श्रीमति डॉ. एकता ताम्रकार के द्वारा प्राकृतिक एवं जैविक खेती, पंकज मिंज द्वारा डिप एवं स्पिंकलर पद्धति द्वारा जल प्रबंधन पर उद्बोधन दिया गया। जिसके पश्चात् आईएफएमसीओ के प्रबंधक नवीन तिवारी द्वारा नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के उपयोग फसलों में

करने की विधि के बारे में विस्तृत बताया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिला प्रबंधक अवनीश सिंह द्वारा फसल क्षतिग्रस्त होने पर फसल की बीमा कराने हेतु किस प्रक्रिया को अपनाना है इसकी जानकारी दी गई। कृषि विभाग कोटा के द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत सरसों बीज का वितरण मुख्य अतिथियों के माध्यम से नगपुरा, डंडबछली एवं तुलफ ग्राम के 20 कृषकों को किया गया। पशु विभाग कोटा से पशु चिकित्सा सहायक सलगय द्वारा पशुओं की मौसमी बीमारी एवं उनके उपचार के बारे में कृषकों को अवगत

कराया गया। ग्राम कसईबहरा ग्राम के बच्चों के द्वारा स्वागत गीत के साथ शुभारंभ किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया तत्पश्चात् पुरस्कार वितरण किया गया, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता में नगपुरा टीम को प्रथम एवं लमरी डबरी टीम को द्वितीय स्थान दिया गया, रंगोली प्रतियोगिता में सरस्वती मरावी को प्रथम पुरस्कार दिया गया, नृत्य प्रतियोगिता में सुआ नृत्य को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार फिल्मी गीत पर किये गये छात्रों को, तृतीय पुरस्कार कुमारी अराध्या पैकरा को एवं चतुर्थ पुरस्कार नगपुरा के बच्चों को दिया गया।

वन मंत्री कश्यप से एसईसीएल के सीएमडी ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप से आज नया रायपुर स्थित उनके निवास, कार्यालय में एसईसीएल के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) श्री हरीश दुहन ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान एसईसीएल के डायरेक्टर (एचआर) श्री बिरंची दास भी उपस्थित थे। भेंट के दौरान वन मंत्री श्री कश्यप को सीएमडी श्री दुहन ने एसईसीएल द्वारा राष्ट्र निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा और छत्तीसगढ़ में किए जा रहे सी एस आर आधारित विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने आश्चर्य किया कि एसईसीएल प्रदेश के सर्वांगीण विकास और समुदायों के उत्थान के लिए आगे भी निरंतर कार्य करता रहेगा। मंत्री श्री केदार कश्यप ने एसईसीएल के योगदान की सराहना की और कहा कि कंपनी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।



तकनीक, प्रशिक्षण और संसाधन के साथ-साथ जागरूकता पर भी देना होगा ध्यान - हरीश दुहन

बिलासपुर । दिनांक 01 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक आयोजित वार्षिक कोयला खान सुरक्षा पखवाड़ा 2025 का उद्घाटन दिनांक 01.12.2025 को एसईसीएल मुख्यालय प्रांगण में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने निदेशक तकनीकी (संचालन) एन. प्रैकलिन जयकुमार, निदेशक (कार्मिक) बिरंची दास, मुख्य सतर्कता अधिकारी हिमांशु जैन, विभिन्न विभागाध्यक्षों, अधिकारियों-कर्मचारियों, विभिन्न श्रमसंघ प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुरक्षा ध्वज फहराकर किया गया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हरीश दुहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को मिलकर शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति

के लिए लगातार प्रयास करते रहने होगा। हम सभी को जाने-अनजाने कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी या हमारे साथियों की जान जोखिम में पड़ जाए और सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी इस विचारधारा के साथ हमें कार्यानिष्ठादन करना होगा। खदान में शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें हरसंभव प्रयास करना होगा और खदानों में कर्मियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। निदेशक तकनीकी (संचालन) एन. प्रैकलिन जयकुमार ने कहा कि सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सुरक्षा लक्ष्य के प्राप्ति के लिए कार्यसंस्कृति में अनुशासन और अभिवृत्ति (एटीट्यूड) पर जोर दिया।

10 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न

रायपुर । दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ योग आयोग के तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय जिला स्तरीय योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, दंतेवाड़ा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण के 5वें व 6वें दिवस में श्री दावड़ा विश्वविद्यालय, नया रायपुर (छ.ग.) के योग विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. खोमेश साहू ने 100 प्रतिभागियों को विशिष्ट योगाभ्यास एवं योग का प्रशिक्षण दिया। सुबह के सत्र में उन्होंने सूर्य नमस्कार तथा अन्य योगिक अभ्यास कराते हुए प्रतिभागियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया। दोपहर के सत्र में उन्होंने अष्टांग योग पाठ्यक्रम अंतर्गत प्रत्याहार एवं धारणा की अवधारणाओं को सरल शब्दों में समझाया। इसके पश्चात 6वें दिन के व्याख्यान में पंचतत्व विषय पर विस्तारपूर्वक क्लास लेते हुए प्रशिक्षणार्थियों को गहन आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवगत कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छत्तीसगढ़ योग आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा, सचिव गौरव देवांगन, परिवीक्षा अधिकारी रविकांत कुंभकार, ब्रांड एंबेसडर एवं योग विशेषज्ञ डॉ. ज्योति साहू, डॉ. सी. एल. सोनवानी, छबिराम साहू, लच्छूराम निषाद।

हर बेटी-बेटा को शिक्षित करना ही समाज को देगा मजबूती, सामुदायिक भवन के प्रथम तल का किया लोकार्पण आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ के बोईरदादर में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने समाज की मांग पर 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन के प्रथम तल का लोकार्पण किया। समाज के वरिष्ठजनों ने मुख्यमंत्री का पापरिक रीति-रिवाजों के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कंवर समाज के पुरोधाओं को नमन करते हुए कहा कि समाज का विकास शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में सफल बनने का माध्यम भी है। हर बेटा-बेटी को शिक्षित करना ही समाज को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आदिवासियों एवं क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने जनजातीय समाज के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर जनजातीय समुदाय के सम्मान को नई ऊंचाई दी है। उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष और पीएम जनमन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह आदिवासी कल्याण के क्षेत्र



में आजादी के बाद सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं जनजातीय परिवारों को उपलब्ध करायी जा रही है। इन योजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में तेज गति से विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की रजत जयंती समारोह के अवसर पर रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक सह संग्रहालय का लोकार्पण किया है। संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के वीर सेनानियों का देश के लिए योगदान जीवंत रूप में प्रदर्शित हो रहा है। यह आने वाली पीढ़ियों को हमारे

वीर नायकों के शौर्य और बलिदान से परिचित कराता रहेगा। यह हमारे आदिवासी समाज के लिए भी गौरव की बात है। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 वर्ष पूरे होने पर राज्य के विकास-पीडीएस प्रणाली, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के व्यापक विस्तार का उल्लेख करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के बाद गांव-गांव तक पहुंच मार्ग और विकास की रोशनी पहुँची है। राज्य में नक्सलवाद विकास में सबसे बड़ी बाधा रहा है, लेकिन सरकार के प्रयासों से यह अंतिम सांस ले रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 31

मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति के बारे में उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हम उद्योग धंधों के माध्यम से युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार प्रदेश के सभी समाज को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ

कीं, जिनमें कंवर समाज के लिए बोईरदादर रायगढ़ मे एक और सांस्कृतिक भवन के साथ मुख्य मार्ग तक सीसी रोड का निर्माण, लैलूंगा के टुरटूरा में नए समाजिक भवन, लैलूंगा और घरघोड़ा में निर्मित सामाजिक भवन के विस्तार की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, लोकसभा सांसद श्री राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, महापौर श्री जीवधन चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार, श्री भरत साय, श्री सत्यानंद राठिया, श्री अनंतराम पैकरा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 11 बीएलओ हुए सम्मानित

रायपुर । जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एस.आई.आर.) के तहत रायपुर नगर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 49 के 11 बीएलओ ने उत्कृष्ट एवं समयबद्ध कार्य करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया। उनके इस सराहनीय प्रदर्शन पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर निगम आयुक्त विश्वदीप ने आज उन्हें शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मानित बुध लेवल अधिकारियों में जोन 8 के मतदान केन्द्र 09 की बीएलओ तिहार राम सोनवानी, मतदान केन्द्र 42 की बीएलओ शीला मुगा, जोन 01 के मतदान केंद्र 91 की बीएलओ मंजु पात्रो, मतदान केंद्र 94 की बीएलओ वीरेंद्र कौशिक, मतदान केंद्र 97 के बीएलओ आत्माराम साहू, मतदान केंद्र 107 के बीएलओ संतराम ध्रुव, मतदान केंद्र 116 की बीएलओ लक्ष्मी खोब्रागड़े, मतदान केंद्र 124 के बीएलओ बसंत प्रधान, मतदान केंद्र 127 की बीएलओ मिथलेश ठाकुर, मतदान केंद्र 129 की बीएलओ दीपिका साहू और मतदान केंद्र 130 के बीएलओ ई. लक्ष्मण राव शामिल हैं। इस अवसर पर अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर, जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल, जोन कमिश्नर दिव्या चंद्रवंशी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से बदलेगी शहरों की सूरत –सीरत

13 नगर निगमों में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429.45 करोड़ के 26 कार्य मंजूर

रायपुर । छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगमों में लागू किया गया है। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इन्में मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सिजोन-कम-स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाइटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कोरीडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाइपास एवं चौड़ीकरण जैसे वृहद कार्य शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों के लिए संबंधित फर्स को कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। वहीं पांच कार्यों



का भूमिपूजन भी हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के बारे में कहा कि इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा। शहरों के सतत विकास और नागरिक केंद्रित समाधानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना तैयार की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी। शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ़लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना को अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है। पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है। चरणबद्ध रूप से

इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। योजना के माध्यम से शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर सुगम यातायात के लिए मुख्य सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, बाइपास सड़क, फ्लाई-ओवर्, सर्विस-लेन, अंडर-पास तथा अन्य विकास का उदाहरण बन सके। पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का भी निर्माण योजना के तहत किए जाएंगे। योजना में ऐसे आइकॉनिक कार्य व परियोजनाएँ ली जाएंगी जो शहर के विकास का उदाहरण बन सकें। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से होंगे ये काम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से प्रमुख रूप से मुख्य सड़क निर्माण एवं मुख्य सड़क चौड़ीकरण कार्य, बाइपास रोड निर्माण, मुख्य सड़क में सर्विस रोड निर्माण कार्य, फ्लाई-ओवर् निर्माण कार्य, अंडर-पास सड़क निर्माण कार्य, जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवेज नेटवर्क निर्माण कार्य, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य, मुख्य सड़कों में रोटीरी चौक निर्माण, पुनर्व्यवस्था कार्य, स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैंड निर्माण, ऑडिटोरियम निर्माण, भव्य उद्यान विकास एवं रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट कार्य तथा पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य किए जाएंगे।

कांग्रेस में असभ्य भाषा का प्रयोग करने की मची है होड़ : पाण्डेय

भाजपा मुख्य प्रदेश प्रवक्ता व सांसद पाण्डेय ने बिलासपुर के घटनाक्रम 0को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला



रायपुर । रातीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने बिलासपुर में कांग्रेस नेताओं द्वारा जुते-चप्पल दिखाकर असभ्य भाषा के प्रयोग को कांग्रेस की पतित होती जा रही राजनीतिक संस्कृति का परिचायक बताया है। श्री पांडेय ने कहा कि लगातार हार से बौखलाई कांग्रेस के लोग अब सार्वजनिक रूप से अपने संस्कारों, आचरण और विचारों के पतन की पराकाष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस को अपने इस अलोकतांत्रिक व अमर्यादित आचरण के लिए प्रदेश की जनता से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेसियों ने संवैधानिक गरिमा को तार-तार कर जन भावनाओं को अपमानित किया है। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद श्री पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों ने अपने उन्हीं राजनीतिक संस्कारों का प्रदर्शन बिलासपुर में किया जो उन्हें केंद्रीय से लेकर प्रदेश नेतृत्व से विरासत में मिले हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को मौत

का सौदागर कहकर जिस असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया, उन्हीं शब्दों का प्रयोग आगे चलकर मोदी की मौत, मोदी की बोटी बोटी काटने तक जा पहुँची और अब राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रति अशिष्टता की सारी हद्द लांघ रहे हैं और इसकी पराकाष्ठा तब हुई जब बिहार में श्री मोदी की माताजी को दी गई अपशब्दों का प्रयोग पूरे देश ने देखी और सुनी। श्री पांडेय ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व की चापलूसी करके आलाकमान की नजर में अव्वल बने रहने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी असंसदीय परंपरा को आगे बढ़ाया और उनकी देखा-देखी प्रदेश के कांग्रेस नेता और पदाधिकारी भी न केवल भाषा का संयम खो रहे हैं अपितु अशिष्ट आचरण की हद्दें पार कर रहे हैं। सांसद पांडेय ने कहा कि कांग्रेस का यह आचरण प्रदेश के जनादेश का अक्षम्य अपमान है।

स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने का अनूठा प्रयास

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मंशानुरूप स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने तथा छत्तीसगढ़ के पर्यटन को नई पहचान देने हेतु जिला प्रशासन रायपुर एवं ईंजु माई ट्रिप द्वारा संचालित नवाचार प्रोजेक्ट पर्यटन साथी का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ। 01 अक्टूबर 2025 को शासकीय आईटीआई सड्डू, रायपुर में प्रारंभ हुए इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का, 30 नवंबर 2025 को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर आयोजित समापन कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज 62 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र एवं ईंजु ट्रिप प्लानर, नई दिल्ली की ओर से जॉब ऑफ़ लेटर प्रदान किए। कुल 123 युवाओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया था। 120 घंटे का व्यापक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत युवाओं को पर्यटन उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें स्थानीय संस्कृति, खान-पान एवं ऐतिहासिक महत्व, सांस्कृतिक संवेदनशीलता एवं व्यवहार, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बुकिंग एवं साइबर सुरक्षा, आपातकालीन प्रोटोकॉल व सुरक्षा नियम, ग्राहक सेवा उत्कृष्टता एवं संचार कौशल, व्यावसायिक नैतिकता एवं आचरण शामिल है। प्रमाण पत्र वितरण के अवसर पर कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि ज्ञान आवश्यक है, लेकिन आपका व्यवहार ही आपका व्यवसाय तय करता है। टूरिस्ट गाइड के रूप में आपका सकारात्मक व्यवहार आपको आगे बढ़ाएगा और नए अवसर प्रदान करेगा। पर्यटन क्षेत्र रिलेशन बिल्डिंग पर आधारित है, इसलिए विशेषज्ञता और विनमता दोनों आवश्यक हैं। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों से भोमदेव, राजिम और सिरपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर प्रश्न पूछकर उनका प्रायोगिक ज्ञान भी परखा। कलेक्टर ने युवाओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मेहनत कीजिए, अपनी हुनर से दुनिया जीतिए। नए-नए कौशल सीखते रहें और अपने व्यवसाय में नवाचार जोड़ते रहें। ईंजु माई ट्रिप के एकेडमिक हेड सुनील अरोरा ने बताया कि प्रशिक्षुओं को एंजेंट लॉगिन आईडी भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे स्वयं के पर्यटन व्यवसाय की शुरुआत भी कर सकते हैं।

मुख्य बजट 2025-26 की एक और बड़ी घोषणा पूर्ण, 46.49 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुसार नवा रायपुर में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला सह एपेन्डीए भवन के निर्माण के लिए राय सरकार ने 46 करोड़ 49 लाख 45 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुरूप इस महत्वपूर्ण परियोजना से प्रदेश में खाद्य एवं औषधि परीक्षण क्षमता को नई मजबूती मिलेगी।नवीन इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला तथा नवीन एफ.डी.ए. भवन का रायपुर में स्थापना करने हेतु शासन द्वारा वर्ग फीट क्षेत्र में (भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) में निर्मित होगा। इसके निर्माण से



लगभग 5 हजार वर्ग फीट (भूतल, प्रथम एवं द्वितीय तल) में संचालित है। प्रस्तावित नवीन प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों (ड्रा एवं इनफर्मेसमेंट) से सुसज्जित होगा तथा 30 हजार वर्ग फीट क्षेत्र में (भूतल, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल) में निर्मित होगा। इसके निर्माण से

रासायनिक परीक्षणों की जांच क्षमता 5000000 नमूने प्रतिवर्ष से 70000000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएगी। माइक्रोबायोलॉजिकल परीक्षण (इंजेक्शन, आई ड्रॉप आदि) 2000 नमूने प्रतिवर्ष होंगे, मेडिकल डिवाइसेस (हाथ के दस्ताने, कैथेटर आदि) जिनका वर्तमान में

परीक्षण नहीं किया जा रहा है उनका भी 500 नमूने प्रतिवर्ष लिए जाएंगे। इसके साथ ही फर्मास्यूटिकल्स नमूनों की जांच 50 से बढ़कर 1000 नमूने प्रतिवर्ष हो जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रयोगशाला राज्य में खाद्य सुरक्षा के ढांचे की और मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक आसान, पारदर्शी और प्रभावी होगी। सरकार जनता को शुद्ध, प्रमाणित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य उत्पाद एवं दवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि नवा रायपुर में बनने वाली यह आधुनिक प्रयोगशाला राज्य के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला के रूप में विकसित होगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।